सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 329 नई दिल्ली, मंगलवार 03 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

झुंझुनूं में हादसा : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 8 मजदूरों की मौत

छापोली में कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गई मशीन के बिजली लाइन की चपेट में आने से वहां काम कर रहे मजदूर करंट की चपेट में आ गए

सीएम भजनलाल ने जताया दुख

सीएम भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, झुंझुनूं में हुए हादसे में करंट लगने से श्रमिकों की असामयिक मृत्यु का समाचार दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घटना की जांच के निर्देश दिए हैं।



झुंझुनूं.एजेंसी

झुंझुनूं जिले के छापोली में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हैं और प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, छापोली में कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गई।

मशीन के बिजली लाइन की चपेट में आने से वहां काम कर रहे मजदूर करंट की चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। प्रशासन की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तथा हादसे की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार, प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, अशोक गहलोत ने हादसे की जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में हुए हादसे में लोगों की मृत्यु पर शोक जताया



राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी इलाके के चापोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ित के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, 'राजस्थान के झुंझुनूं में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हो। जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।' इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने और घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने हादसे पर दुख जताते हुए 'एक्स' पर लिखा, ''झुंझुनूं में हुए हादसे में करंट लगने से श्रमिकों की असामयिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुणे को बड़ा तोहफा

आज 21,800 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी

नई दिल्ली.एजेंसी



• नए मेट्रो कॉरिडोर मौजूदा पुणे मेट्रो नेटवर्क और इंटरसिटी बस सेवाओं के साथ जुड़ेंगे, जिससे शहरी कनेक्टिविटी बढ़ेगी
• पुणे मेट्रो लाइन-3 केवल महिला ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा संचालित की जाएगी, बिजली की लगभग 30 प्रतिशत जरूरतों को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3 नवंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित पुणे मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन करेंगे, जिसे पिंक लाइन के रूप में भी जाना जाता है। यह परियोजना तकनीकी नवाचार और आधुनिक परिवहन समाधानों के माध्यम से पुणे के शहरी आवागमन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लगभग 23 किलोमीटर तक फैली पिंक लाइन मान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। यह कॉरिडोर हिंजेवाड़ी आईटी हब और शिवाजीनगर के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, पुणे के प्रमुख रोजगार केंद्रों में से एक तक पहुंच में सुधार करेगा और हजारों आईटी पेशेवरों और अन्य यात्रियों के दैनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। यह कॉरिडोर मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ एकीकृत होगा, जिससे पुणे के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। यह निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने, यातायात की भीड़ और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और प्रमुख वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा।

पिंक लाइन की एक उल्लेखनीय विशेषता महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के समावेशन को लेकर उनके अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पर जोर देना है। यह लाइन पूरी तरह से महिला ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा संचालित की जाएगी, जिससे यह अपनी तरह की पहली पहल बन जाएगी। यह परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता पर भी जोर देती है, इसकी कुल बिजली आवश्यकताओं का लगभग 30 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे लगभग 13,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में पुणे मेट्रो लाइन 2ए, 2बी, 4 और 4ए शामिल हैं, जो शहर के मेट्रो नेटवर्क का काफी विस्तार करेगी और महत्वपूर्ण आवासीय, वाणिज्यिक और आईटी केंद्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।

यूपी में बड़ा सड़क हादसा : कुशीनगर में वैन और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत



कुशीनगर.एजेंसी

हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। पेट्रोल पंप के पास वैन और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह दुर्घटना देर रात उस समय हुई जब सभी लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायल किशोर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भलुही गांव के निवासी वैन में सवार थे। प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया प्रसाद (40) भी इनमें शामिल थे। उनके पिता रामबेलास (65) भी वैन में थे। राममिलन (35), आयुष (12), मृदुल मिश्रा (37) और रंजय गुप्ता (35) भी साथ थे। मिथिलेश गुप्ता (22) भी इस समूह का हिस्सा थे। वैन में सवार इन सात लोगों में से छह की मौत हो गई। राममिलन का 17 वर्षीय पुत्र आर्यन गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग देवराज पिपरा में एक रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से देर रात वे अपने गांव लौट रहे थे। हाटा कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास यह दुखद घटना हुई। सामने से आ रहे एक ट्रेलर से उनकी वैन टकरा गई।

मुख्यमंत्री नायब सैनी से हरियाणा निवास में पंजाब के उद्योगपतियों ने की मुलाकात

हरियाणा में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी : मुख्यमंत्री



ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। के मुख्यमंत्री नायब सैनी से सोमवार को हरियाणा निवास में पंजाब से आए उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की आवश्यक स्वीकृतियां एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा उद्योगों की जरूरत के अनुसार औद्योगिक भूमि भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि निवेशकों को अपना कारोबार स्थापित करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लगातार उद्योगपतियों के संपर्क में रहकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। हरियाणा में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति शामिल थे। उन्होंने हरियाणा में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और निवेश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की।

दिल्ली-NCR में दीपावली पर 7 और 8 नवंबर को जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सीमित छूट

नई दिल्ली.एजेंसी



दीपावली पर दिल्ली-NCR के लोगों को पटाखे जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने कुछ सख्त शर्तों के साथ 7 और 8 नवंबर 2026 को प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह छूट केवल तय समय के लिए होगी। 9 नवंबर से क्षेत्र में पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर को दिए आदेश में ग्रीन पटाखों के सीमित निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी।

अदालत का उद्देश्य दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दीपावली की परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इन इलाकों को नो-क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ CSIR-NEERI से प्रमाणित और PESO से अनुमोदित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और बिक्री की जा सकेगी। इनका निर्माण 2 से 6 नवंबर तक होगा। प्रत्येक पैकेट पर उत्पाद और बैच से जुड़ा QR कोड लगाना अनिवार्य होगा, ताकि निर्माता, पंजीकरण और परीक्षण प्रमाणपत्र की जानकारी हासिल की जा सके।

मुख्यमंत्री धामी ने किया देवभूमि परिवार पोर्टल का शुभारंभ

ओ पी उनियाल/ओपन सर्च

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में 'देवभूमि परिवार पोर्टल' एवं 'विकसित उत्तराखण्ड विजन-2047' का लोकार्पण किया और देवभूमि परिवार आईडी के सृजन की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हुए 'एक परिवार, एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म' की अवधारणा को साकार किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही विकसित उत्तराखण्ड विजन-2047 दस्तावेज के माध्यम से वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने का दीर्घकालिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात

नई दिल्ली.एजेंसी



रक्षा मंत्री ने एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित को नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित का कार्यकाल अच्छा रहेगा

भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने 2 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री के साथ उनकी यह पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित से मुलाकात की। उन्होंने एयर चीफ मार्शल दीक्षित को एक विशिष्ट वायु योद्धा बताते हुए कहा कि वे अपने उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। रक्षा मंत्री ने एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित को नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित का कार्यकाल अच्छा रहेगा। बता दें कि एयर चीफ मार्शल बनने के बाद अशुतोष दीक्षित को 1 नवंबर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित वायुसेना के नए चीफ बने हैं। इससे पहले वह वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कमान संभालने पर सम्मान और गर्व जताया था। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया था। उन्होंने निवर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के नेतृत्व में वायुसेना ने दिखाया कि सटीक और निर्णायक हवाई शक्ति क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उन्हें पूरी तरह तैयार वायुसेना की कमान सौंपी है। इस बीच सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने 8 युद्धपोतों के निर्माण और खरीद के लिए कुल 53,866.50 करोड़ रुपए के करार किए हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण इकोसिस्टम के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है।

'राहुल गांधी मॉक पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं', हैदराबाद से अमित शाह का करारा तंज

कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद भाजपा राजधानी दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्राएं निकाली

हैदराबाद.एजेंसी



सरदार पटेल उस वक्त निजाम को न झुकाते, तो हैदराबाद आज भारत का हिस्सा नहीं होता। कल दिल्ली में भी एक रैली हुई थी। वो (विपक्ष) कहते हैं कि ये वोट बचाओ रैली है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वोट बचाओ रैली नहीं थी बल्कि घुसपैठिया बचाओ रैली थी : अमित शाह

इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद भाजपा राजधानी दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत ताबड़तोड़ पदयात्राएं निकाल रही है।

इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हैदराबाद में पदयात्रा निकाली। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल उस वक्त निजाम को न झुकाते, तो हैदराबाद आज भारत का हिस्सा नहीं होता। कल दिल्ली में भी एक रैली हुई थी। वो (विपक्ष) कहते हैं कि ये वोट बचाओ रैली है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वोट बचाओ रैली नहीं थी बल्कि घुसपैठिया बचाओ रैली थी। कांग्रेस एसआईआर को रोककर देश की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को जितना जोर लगाना है, लगाने दो, भाजपा एक-एक घुसपैठिए को मतदाता सूची और देश से बाहर निकालकर ही दम लेगी। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी कांग्रेस एंड कंपनी एसआईआर को रोकने में लगी है, क्योंकि ये घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं, लेकिन भाजपा एसआईआर के साथ मजबूती से खड़ी है। अब इस देश में वही वोट डालेगा, जो इस देश का नागरिक होगा।

राहुल गांधी कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर 13 करोड़ लोगों के वोट काट दिए गए हैं, लेकिन यह झूठ है क्योंकि 13 करोड़ वोट में से सवा छह करोड़ वोट ऐसे हैं, जो दूसरी जगह रहने चले गए हैं, क्या किसी को दो जगह वोट देने का अधिकार मिल सकता है? इसमें से 2.8 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 7 दिसंबर तक 'लीव इंडिया' नोटिस पर रोक

मुंबई.एजेंसी

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत में रहने और उनके ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की ओर से जारी 'लीव इंडिया' नोटिस पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का फैसला किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हालांकि, अदालत ने अभिनेता को कथित तौर पर ओसीआई नियमों के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा कि केवल भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के ओसीआई कार्ड और विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए।

हरियाणा की प्रगति और जनता की खुशहाली हमारी साझा मंजिल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विधानसभा द्वारा संविधान पखवाड़े के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर

ओपन सर्च ब्यूरो







- राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सभी हरियाणा की जनता के प्रतिनिधि
- विधानसभा की गरिमा, जनसंवाद और संवैधानिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने का किया आह्वान
- संविधान पखवाड़े के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक राहें और विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हरियाणा की प्रगति और प्रदेश के लोगों की खुशहाली सभी की साझा मंजिल है। हम सभी की पहचान इस बात से है कि हम हरियाणा की जनता के प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री सोमवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विधानसभा द्वारा संविधान पखवाड़े के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हीरक जयंती के इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति से इसकी गरिमा बढ़ी है और संसदीय प्रक्रियाओं, सदन की मर्यादा तथा जनप्रतिनिधियों के दायित्वों पर उनका मार्गदर्शन सभी के लिए मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि हीरक जयंती समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु ने पधार कर हरियाणा की जनता को अपना आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की 60 वर्षों की विकास यात्रा केवल सड़कों, संस्थानों और उद्योगों के विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों की मेहनत भी शामिल है।

खेतों की हरियाली से उद्योगों की ऊंचाइयों तक, गांवों की पगडंडियों से आधुनिक एक्सप्रेस-वे तक और अखाड़ों की मिट्टी से विश्व के खेल मंचों तक हरियाणा ने अपने परिश्रम, साहस और संकल्प से प्रगति के नए अध्याय लिखे हैं। प्रदेश की उपलब्धियों की नींव उन चर्चाओं, निर्णयों और कानूनों से भी पड़ी है, जिन्हें जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में आकार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था और उस समय विधानसभा में 54 सदस्य थे। वर्ष 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या 81 हुई और वर्ष 1977 में बढ़कर 90 हो गई। उन्होंने कहा कि इन सीटों में आज बढ़ोतरी की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं सुलभ हो सकें। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश 15वीं विधानसभा के दौर में अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व के विस्तार और जनता की आकांक्षाओं के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं।

उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर, 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। उस समय संसाधन सीमित थे और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़क तथा प्रशासनिक व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना बड़ी चुनौती थी। उन्होंने उन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने इन परिस्थितियों में प्रदेश के भविष्य की मजबूत नींव रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान हमारे निर्णयों और आचरण में दिखाई देना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श निहित हैं। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन आदर्शों को शासन के व्यवहार में उतारें। जब पात्र नागरिक को बिना भेदभाव उसका अधिकार मिलता है, कमजोर व्यक्ति की सुनवाई होती है और समाज में परस्पर सम्मान बढ़ता है, तभी इन संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा कानून बनाने, सार्वजनिक धन के उपयोग को स्वीकृति देने और सरकार को जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण मंच है। सदन में उठाया गया सार्थक प्रश्न किसी गांव की समस्या को समाधान तक पहुंचा सकता है और किसी विधेयक पर दिया गया उपयोगी सुझाव लाखों नागरिकों का जीवन बेहतर बना सकता है।

प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, बजट चर्चा और समितियों का कार्य संसदीय व्यवस्था को जीवंत बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए अध्ययन, तैयारी और जनता से निरंतर संपर्क आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जवाबदेही शासन को मजबूत बनाती है। विपक्ष द्वारा उठाई गई जनहित की बात को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है।

12 नवंबर को जिले में आयोजित होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम



ओपन सर्च ब्यूरो

करनाल। एडीसी डॉ. राहुल रईया ने कहा कि जिले में 12 नवंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिलेभर में लगभग 4 लाख 50 हजार बच्चों, किशोरियों एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। यह दवा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 12 नवंबर को किसी कारणवश दवा लेने से वंचित रह जाने वाले लाभार्थियों को 19 नवंबर को मॉप-अप राउंड के दौरान दवा दी जाएगी। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल और समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाएं।

एडीसी डॉ. राहुल रईया सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही स्कूलों की चेकिंग भी की जाए, ताकि कोई भी स्कूल इस अभियान से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में आयोजित होने वाली पीटीएम के दौरान अभिभावकों को भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के महत्व एवं इसके उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान को लेकर व्यापक जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग कि अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। एडीसी ने कहा कि बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों तक दवा पहुंचाना सुनिश्चित करें।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता की एकजुटता महत्वपूर्ण संदेश : सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो

नई दिल्ली/सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि देश की जनता अपने मताधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर सजग है।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित महारैली ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्रमुखता से सामने रखा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब मिलना लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने और नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। सांसद ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष किसी संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुमारी सैलजा ने हरियाणा, उत्तराखंड सहित देशभर से महारैली में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस अपनी आवाज सड़क से संसद तक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से उठाती रहेगी। सांसद ने कहा कि हमारा संकल्प स्पष्ट है मताधिकार सुरक्षित रहेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा।

करनाल सहकारी चीनी मिल की प्रबंध निदेशक ने पांच राजकीय विद्यालयों का किया निरीक्षण

ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। हरियाणा सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से आज करनाल सहकारी चीनी मिल की प्रबंध निदेशक अदिति ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दहा, बजीदा जाटान, कैलाश, टिकरी एवं टपराना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दहा का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों द्वारा करवाई जा रही शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी पढ़ाई एवं शैक्षणिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यालय की कक्षाओं, स्वच्छता व्यवस्था एवं स्कूल परिसर का निरीक्षण किया तथा प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके उपरांत प्रबंध निदेशक ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बजीदा जाटान पहुंचकर मिड डे मील योजना के तहत तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया।

उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन भी ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनमें अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रहित की भावना विकसित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैलाश, टिकरी एवं टपराना का भी निरीक्षण किया। इन विद्यालयों में उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता, विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं, कक्षाओं में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी तथा विद्यालयों में संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। प्रबंध निदेशक ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में स्वच्छता, अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

समाधान शिविर में डीडीपीओ मनीष मलिक ने सुनीं शिकायतें, अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर दिए समाधान के निर्देश

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। लघु सचिवालय के प्रथम तल पर सोमवार को डीडीपीओ मनीष मलिक की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया।



शिविर में मनीष मलिक ने आमजन की विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान सुनिश्चित करें, ताकि शिकायतकर्ताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से सोनीपत के सेक्टर -15 से रेन वाटर सीवरेज हॉल की मरम्मत करवाने, गांव लाठ से निशान देही करके प्लॉट की जमीन पूरी किए जाने, कैलाश कॉलोनी निवासी की रूकी हुई पेंशन जारी करवाने, सैनीपुरा कॉलोनी से गली के अंदर डीलर द्वारा गेट न लगवाने, गांव सलीमसर माजरा से ग्राम पंचायत की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने, गांव हुल्लाहेड़ी से सरकारी रास्ते व जौहड़ से अवैध कब्जा हटवाने की शिकायत प्राप्त हुई। इसके अलावा गांव बिंदरोली से गांव भौवापुर तक जाने वाली सड़क बनवाने व पानी की निकासी के लिए नाला बनवाने की शिकायत दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त पेंशन और फैमिली आईडी से संबंधित शिकायतें दर्ज हुई।

संविधान की भावना सदन से गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचे : संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा और देश की एकता का आधार है। यह नागरिकों को अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। संविधान की भावना केवल सदन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे गांवों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

वे सोमवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित संविधान पखवाड़े के तहत जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री नायब सैनी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और अधिकारियों का अभिनंदन किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। संविधान निर्माताओं और संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहां प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार मिले तथा सभी को सम्मान और समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों और जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण मंच है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनका मानना है कि सदन की गरिमा बनाए रखना, संसदीय मर्यादाओं का पालन करना और जनहित के विषयों पर स्वस्थ चर्चा व सार्थक संवाद करना ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सदस्यों के विचार और मत अलग हो सकते हैं, लेकिन जनहित और प्रदेश का विकास सभी का साझा उद्देश्य होना चाहिए। सदन में सहमति-असहमति हो सकती है, लेकिन आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संविधान पखवाड़े के अवसर पर सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि संविधान के आदर्शों, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय गरिमा को सर्वोपरि रखेंगे।

जनसेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से हरियाणा को विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सभी मिलकर योगदान देंगे। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा कि संविधान हमारा गौरव है, लोकतंत्र हमारी शक्ति है और जनसेवा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। इसी भावना के साथ उन्होंने सभी को संविधान पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं।

19 व 20 नवंबर को डीसीआरयूएसटी यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2026

ओपन सर्च ब्यूरो



सोनीपत। जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2026 का आयोजन 19 व 20 नवंबर को मुरथल स्थित दीन बंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) में किया जाएगा। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को लघु सचिवालय में सीटीएम सिमरन की अध्यक्षता में प्राथमिक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों, प्रोफेसरों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सीटीएम सिमरन ने महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने संस्थानों से जूरी सदस्यों के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम की सिफारिश भेजें। इसके अलावा मंच संचालन (एंकरिंग) के लिए भी युवाओं के नाम भेजने के लिए कहा गया। सीटीएम सिमरन ने बताया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव में 15 से 29 वर्ष तक की आयु का कोई भी युवा भाग ले सकता है। इसके लिए प्रतिभागी का सोनीपत जिला का निवासी होना अथवा जिला के किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर मंच प्रदान करेगा। इसलिए सभी शिक्षण संस्थान अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।

हरियाणा में कक्षा VI से XII तक के छात्रों के लिए स्कूल-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सहायता की योजना

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अपने प्रस्तावित 'साथ' प्रोजेक्ट के तहत कक्षा VI से XII तक के विद्यार्थियों के लिए एक व्यवस्थित स्कूल-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा के तनाव, चिंता (एंजाइटी), अवसाद (डिप्रेशन), बुलिंग, सामाजिक अलगाव और अत्यधिक स्क्रीन उपयोग सहित विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं की समय रहते पहचान करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इसमें स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्र स्वयंसेवकों, परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों



(क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट) और मनोचिकित्सकों (साइकियाट्रिस्ट) को शामिल करते हुए एक समन्वित तंत्र की परिकल्पना की गई है।

प्रस्तावित रूपरेखा के तहत पेशेवर सहायता प्रणाली के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य विभाग के 122 परामर्शदाताओं को चिह्नित किया गया है। इसमें मनोविज्ञान की योग्यता वाले शिक्षकों और विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भागीदारी भी शामिल है, ताकि पेशेवर मदद की आवश्यकता वाले छात्रों को समय पर सहायता मिल सके। विद्यार्थियों की अलग-अलग विकासात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कक्षा VI से VIII और कक्षा द्वादश से XII के छात्रों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा VI से VIII के छात्रों के लिए ध्यान मुख्य रूप से भावनात्मक जागरूकता, आत्मविश्वास, किशोरावस्था से जुड़े बदलावों, परीक्षा की चिंता, बुलिंग, साथियों द्वारा उपेक्षा और माता-पिता के साथ बातचीत में आने वाली कठिनाइयों पर केंद्रित होगा। शिक्षकों को शुरुआती लक्षणों—जैसे लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, लोगों से दूरी बनाना, दिनचर्या के कार्यों में रुचि कम होना, एकाग्रता की कमी, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट और स्कूल जाने में आनाकानी—की पहचान करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा।

शहीद स्मारक के 5 नवंबर को उद्घाटन को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। अंबाला छावनी में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के 5 नवम्बर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन को लेकर अम्बाला जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में शहीद स्मारक में बैठक हुई जिसमें सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव के. मकरंद पांडुरंग के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान अधिकारियों ने शहीदी स्मारक का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बैठक के दौरान कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इससे पहले आयुक्त एवं सचिव के मकरंद पांडुरंग ने शहीदी स्मारक के उद्घाटन से संबंधित कार्यक्रम की तैयारियों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने तथा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को गंभीरता एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी के गांधी ग्राउंड का दौरा कर आगामी 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया।

इस अवसर पर उपायुक्त सचिन गुप्ता भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच, बैठने की व्यवस्था, कलाकारों के लिए मंच, मीडिया गैलरी तथा पार्किंग व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली, पेयजल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अम्बाला छावनी में निर्मित आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक-1857 का लोकार्पण करेंगे और गांधी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

कैट की एलजी से अपील, प्रदर्शनों से बाधित हो रहा व्यापार, दिल्ली के बाहरी इलाकों में बनाए प्रदर्शनस्थल

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण बार-बार होने वाली बाधाओं का जिक्र किया। इसमें उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों, जनसभाओं, प्रदर्शनों और राजनीतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त जगहों की पहचान करें और उन्हें अधिसूचित करें

नई दिल्ली (एजेंसी)



कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों के लिए आधिकारिक जगह तय करें, क्योंकि इनके बार-बार होने से व्यावसायिक गतिविधियों, लोगों की आजीविका और आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ता है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण रुक-रुक कर लेकिन लगातार व्यवधान आ रहे हैं, जिससे बाजार, कारोबार और नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। पत्र में कहा गया है, हालांकि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय दूसरे नागरिकों के अधिकारों और उनकी आजीविका का हनन न हो। पत्र में कहा गया है कि विरोध करने का अधिकार शहर को ठप करने का अधिकार नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही जैसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय व्यापार करने के अधिकार की बलि नहीं दी जा सकती। कैट ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक, थोक और वितरण केंद्रों में से एक है, जहां हजारों बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाखों लोगों की आजीविका का जरिया हैं। इसमें कहा गया है कि बार-बार होने वाली रुकावटों से न केवल व्यापारी और दुकानदार प्रभावित हुए हैं, बल्कि रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले, दिहाड़ी मजदूर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, कर्मचारी, डिलीवरी करने वाले लोग और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं।

संगठन ने बताया कि ट्रैफिक डायवर्जन, सड़कों की नाकेबंदी और व्यावसायिक इलाकों तक पहुंच सीमित होने के कारण, देश के अन्य हिस्सों से आने वाले व्यापारियों और कारोबारियों ने दिल्ली आना कम कर दिया है। इसका असर व्यापारिक लेन-देन पर पड़ा है और सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। एक स्थायी समाधान की मांग करते हुए, कैट ने पांच उपाय सुझाए हैं। इनमें विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगहें घोषित करना, व्यावसायिक और बाजार क्षेत्रों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाना, लोगों की रोजी-रोटी की सुरक्षा करना और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना शामिल है। संगठन ने सुझाव दिया कि दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि विरोध-प्रदर्शन इस तरह से हों कि आम जनता को कोई परेशानी न हो और आर्थिक गतिविधियां भी न रुकें। कैट ने स्पष्ट किया कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी चिंता यह है कि विरोध-प्रदर्शनों की वजह से राष्ट्रीय राजधानी का आर्थिक जीवन पूरी तरह ठप न हो जाए। पत्र में कहा गया है, संविधान शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी देता है। साथ ही, यह किसी भी पेशे को अपनाने या व्यापार करने का अधिकार भी देता है, जिस पर जनहित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इन दोनों सिद्धांतों की सुरक्षा इस तरह से की जानी चाहिए कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। व्यापारी संगठन का कहना है कि विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगहें होने से एक संस्थागत समाधान मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने और आर्थिक गतिविधियों को चलाने, दोनों काम बिना किसी टकराव के साथ-साथ हो सकेंगे। और उन्हें अधिसूचित करें। व्यापारी संगठन ने कहा कि पिछले एक महीने से भी अधिक समय से दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण बार-बार होने वाली बाधाओं का जिक्र किया। इसमें उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों, जनसभाओं, प्रदर्शनों और राजनीतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त जगहों की पहचान करें

'बुद्धिमानों के वचनों पर चिंतन कर कर्म करने वाला पाता है दीर्घकालिक सफलता', पीएम मोदी ने साझा किया सुभाषित

नई दिल्ली (एजेंसी)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर एक सुभाषित शेयर किया गया है, जिसमें यश, सम्मान प्राप्त करने और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का संदेश दिया गया है। पीएम मोदी की ओर से संस्कृत श्लोक, 'सुव्याहृतानि धीराणां फलतः परिचिन्त्य यः। अध्यवस्यति कार्येषु चिरं यशसि तिष्ठति॥' शेयर किया गया है, जिसका हिंदी भावार्थ है कि जो व्यक्ति धीर, बुद्धिमान और विवेकी जनों के सुविचारित वचनों के परिणाम पर विचार करके उनके अनुसार अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करता है, वह दीर्घकाल तक यश और सम्मान प्राप्त करता है तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री की ओर से साझा किया गया यह प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक सनातन धर्म के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत आने वाली 'विदुर नीति' के 39वें अध्याय के 31वें श्लोक से लिया गया है। महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के अधिकारों को लेकर महाराजा धृतराष्ट्र चिंतित थे, तब महात्मा विदुर ने इस श्लोक के माध्यम से उन्हें समझाया था। इस श्लोक के माध्यम से विदुर राजा धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान राजा या मनुष्य को अपने कर्मों का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल ज्ञान की बातें सुनना काफी नहीं है। असली सफलता और चिरस्थायी सम्मान उसे मिलता है जो ज्ञानी लोगों की सीख को समझता है, उस सीख के अच्छे-बुरे दूरगामी परिणामों का आकलन करता है और फिर संकल्प लेकर अपने कर्तव्य-पथ पर आगे बढ़ जाता है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने से अधिक अनुभवी और ज्ञानी लोगों की सलाह लेनी चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मिली राहत खत्म, बढ़ेगा वायु प्रदूषण, गिरने लगा न्यूनतम तापमान

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु प्रदूषण से मिली राहत अब धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई बारिश ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों की हवा को काफी हद तक साफ कर दिया था। कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया था और प्रदूषण का स्तर ग्रीन जोन तक पहुंच गया था। हालांकि, अब मौसम में बदलाव के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक में दोबारा बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे हैं। आशंका है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से खराब श्रेणी में पहुंच सकती है और एक्यूआई लाल निशान के पार जा सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी 2 नवंबर से 7 नवंबर तक के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूरे सप्ताह मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। साफ मौसम और बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों का प्रभाव फिर से बढ़ सकता है।

ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को एक बार फिर प्रदूषित हवा का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 2 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, 3 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंच सकता है। 4 नवंबर को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद 5 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 6 और 7 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आर्द्रता का स्तर भी 60 और 85 प्रतिशत के बीच दर्शाया गया है। पूरे सप्ताह मुख्य रूप से साफ आसमान रहने का अनुमान है। खास बात यह है कि 2 से 7 नवंबर तक किसी भी दिन मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। बारिश के बाद साफ हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा में अब दोबारा प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।

'ठीक से नहीं किया गया', रिजिजू का दावा, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की रैली में जुटी भीड़ की 'एआई फोटो' बनाई

नई दिल्ली (एजेंसी)



केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई 'इंडिया' गठबंधन की रैली में भारी भीड़ दिखाने के लिए एआई से बनाई गई तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि वह भीड़ की संख्या को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए एआई का सहारा ले रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजिजू ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की 'फर्जी नैरेटिव' फैलाने वाली टीम ने रामलीला मैदान के भरे होने को दिखाने के लिए जो एआई फोटो बनाई है, उसे भी ठीक से नहीं बना पाई। रिजिजू ने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें तेलंगाना के एक कांग्रेस सांसद द्वारा पोस्ट की गई फोटो शामिल थी। इस फोटो में विपक्ष की रैली में भारी भीड़ दिखाई गई थी। एक्स पर कई यूजर्स ने भी इस तस्वीर पर सवाल उठाए और इसे एआई से बनाई गई फोटो बताया। इसमें रैली के मंच पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एआई जनरेटेड तस्वीरें थीं, जो असल मंच से काफी अलग दिख रही थी। यह विवाद तब सामने आया, जब भाजपा और कांग्रेस के बीच 'इंडिया' गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली में शामिल लोगों की संख्या को लेकर बहस छिड़ गई। यह रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। रविवार को भाजपा ने इस रैली को 'फ्लॉप शो' करार दिया और दावा किया कि वहां मौजूद भीड़ विपक्ष के दावों के आसपास भी नहीं थी।

वायुसेना प्रमुख मार्शल अशुतोष दीक्षित ने अग्रिम एयरबेस का किया दौरा

नई दिल्ली (एजेंसी)



एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने वायुसेना प्रमुख का पद संभालने के बाद अपने पहले दौरे के तहत एक अग्रिम वायुसेना अड्डे का दौरा किया। खास बात यह है कि वह पहले इस वायुसेना के एयरबेस की कमान स्वयं संभाल चुके हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने अपने दौरे के दौरान एयरबेस की अभियान संबंधी तैयारियों और ऑपरेशनल क्षमताओं की समीक्षा की है। एयर चीफ अशुतोष दीक्षित ने यह भी जाना कि एयरबेस मिशनों को पूरा करने के लिए किस हद तक तैयार है। एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने एयरबेस पर उपलब्ध परिचालन क्षमताओं, संसाधनों और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि जरूरत पड़ने पर एयरबेस निर्धारित अभियानों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने में सक्षम रहे। इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने अग्निवीरवायु से भी बातचीत की। इनमें महिला अग्निवीर वायु भी शामिल थीं। उन्होंने अग्निवीर वायु से संवाद करते हुए वायुसेना की युद्धक क्षमता और अभियान संबंधी प्रभावशीलता को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने महिला अग्निवीर वायु सहित सभी अग्निवीर वायु के योगदान को वायुसेना की परिचालन तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। वायुसेना प्रमुख का यह दौरा अग्रिम मोर्चे पर तैनात वायुसेना कर्मियों के साथ उनके सीधे जुड़ाव और परिचालन परिस्थितियों से लगातार संपर्क बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दौरे के दौरान उनका ध्यान एयरबेस की तैयारियों के साथ-साथ वहां तैनात उन पुरुष और महिला कर्मियों पर भी रहा, जो वायुसेना के विभिन्न अभियानों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने रविवार को गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायुसेना 'वायु' के चार सूत्रों पर काम करेगी। वायुसेना प्रमुख ने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दीं। एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताओं को 'वायु' नाम के चार सूत्रों में बांटा है। इनमें सतर्कता और तत्परता, आत्मनिर्भरता, नवाचार और एकजुट प्रयास शामिल हैं।

नागर विमानन क्षेत्र के लिए नए नियम लागू करेगा केंद्र, 2027 से प्रभावी होंगे 'भारतीय वायुयान नियम'

नई दिल्ली (एजेंसी)



केंद्र सरकार ने देश के नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक नया और व्यापक नियामकीय ढांचा अधिसूचित किया है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और लगभग नौ दशकों से लागू विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।

नए नियम विमानन क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें विमान पंजीकरण, एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन, विमान निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, कर्मियों के लाइसेंस और हवाईअड्डा संचालन से जुड़े विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य विमानन हितधारकों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। नए ढांचे के तहत विमानों के पंजीकरण और एयरवर्थनेस प्रमाणन से संबंधित नियमों को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने के मानदंड शामिल हैं कि कोई विमान संचालन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। नियम विमान डिजाइन, निर्माण मानकों, संशोधनों और मरम्मत से संबंधित स्वीकृतियों को भी कवर करते हैं। सरकार ने विमानों के पूरे परिचालन जीवनकाल के दौरान नियमित निरीक्षण और रखरखाव को अनिवार्य बनाया है। एयरलाइंस और विमान संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान लगातार सुरक्षा मानकों का पालन करते रहें और उनकी एयरवर्थनेस बनी रहे। नए नियमों में पायलटों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों सहित विमानन क्षेत्र के विभिन्न पेशेवरों के लिए योग्यता और लाइसेंसिंग मानकों को भी विस्तार से निर्धारित किया गया है।

इसमें प्रशिक्षण, परीक्षा, अनुभव और चिकित्सीय फिटनेस संबंधी आवश्यकताओं के अलावा लाइसेंस के नवीनीकरण, निलंबन और रद्द करने की शर्तें भी शामिल हैं। एयरलाइन संचालन से जुड़े प्रावधानों में फ्लाइट प्लानिंग, परिचालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर दिया गया है। पायलटों और केबिन क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी और विश्राम अवधि से जुड़े नियम भी शामिल किए गए हैं, ताकि थकान से जुड़े जोखिम कम हों और उड़ान सुरक्षा मजबूत हो सके। यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में टिकट मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता शामिल है।

अगले वर्ष से एयरलाइंस को टिकट की कुल कीमत के साथ उसका विस्तृत ब्योरा भी देना होगा, जिसमें बेस फेयर, कर, शुल्क, रद्दीकरण शुल्क और रिफंड नीति की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइन किराये अब भी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की निगरानी के दायरे में रहेंगे।

पंजाब : आम आदमी पार्टी से निलंबित तीन विधायकों ने थामा भाजपा का दामन

नई दिल्ली (एजेंसी)



आम आदमी पार्टी के निलंबित तीन विधायकों ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन कर ली। विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा ने भाजपा का दामन थामा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, 'भाजपा का काफिला दिनों-दिन बढ़ रहा है।

बड़ी खुशी हो रही है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल की गहराई से उनका धन्यवाद। आम आदमी पार्टी डूबती नाव है।' आम आदमी पार्टी ने अपने दो विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब आम आदमी पार्टी विधानसभा स्पीकर से उनकी सदस्यता भी रद्द करने की मांग करेगी। दोनों विधायकों ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन पंजाब के पटियाला जिले की दो विधानसभा सीटों से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, पार्टी ने कहा था कि इन दोनों विधायकों को कार्रवाई के तहत निकाला गया है। विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह पंजाब विधानसभा में सनौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वह 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। बताया जा रहा है कि उनकी अपनी ही सरकार ने विधायक पठानमाजरा के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ तीखे तेवर अपना लिए थे और अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं, समाना से विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि हाल ही में आई आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। चेतन सिंह जोड़ामाजरा साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर समाना से भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वे भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। वहीं, पार्टी से निलंबित विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी पंजाब विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को अपना इस्तीफा भेज दिया है।

दिल्ली से दो वाहन चोर पकड़े गए, दोपहिया वाहन, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से वाहन चुराने वाले दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी किए गए चार दोपहिया वाहन, चार मोबाइल फोन और दो लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मी नगर के रहने वाले 22 वर्षीय सूरज उर्फ काना और जुबेर को इलाके में स्थित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही, पुलिस ने लक्ष्मी नगर थाने में दर्ज वाहन चोरी के चार मामलों को सुलझा लिया है। यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या ये आरोपी अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, जांच की शुरुआत 4 सितंबर को एक स्कूटर की चोरी के संबंध में दर्ज ई-एफआईआर के बाद हुई। पुलिस टीम ने संदिग्धों की पहचान करने और चोरी हुए वाहन का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गुप्त सूत्रों से जानकारी जुटाई।

अधिकारियों ने बताया कि एक पक्की सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने 31 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय के पास से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और मामले से जुड़ा चोरी का स्कूटर बरामद किया। लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने अन्य वाहन चोरियों में भी अपनी संलिप्तता कबूल की। उनके खुलासों के आधार पर, पुलिस ने लक्ष्मी नगर के विश्वकर्मा पार्क के पास से दो और स्कूटर तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने चार टूटे हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन और दो अलग-अलग ब्रांड के लैपटॉप भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि सूरज उर्फ काना इलाके से दोपहिया वाहन चुराता था और उन्हें जुबेर को बेच देता था, जो इन चोरी के वाहनों को खरीदता था। पुलिस ने बताया कि सूरज ने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसे नशीले पदार्थों की लत है। आठवीं कक्षा तक पढ़ा जुबेर होटलों और कार्यक्रमों में वेटर के तौर पर काम करता है। माता-पिता की मौत के बाद वह अपनी बुआ के साथ रहता है। पुलिस के अनुसार, उसे भी नशीले पदार्थों की लत है।

राजनीतिक आयोजन खत्म हो जाते हैं, लेकिन व्यापारिक नुकसान लंबे समय तक रहता है : इंडिया ब्लॉक रैली पर दिल्ली व्यापार महासंघ

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली व्यापार महासंघ (डीवीएम) ने सोमवार को बीते 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली के बाद व्यापार जगत का दृष्टिकोण सामने रखते हुए कहा है कि यह आयोजन राजनीतिक दलों के लिए अपनी बात रखने और शक्ति प्रदर्शन का अवसर रहा होगा, लेकिन दिल्ली के व्यापारिक समुदाय के लिए इसने कई आर्थिक चिंताएं और सवाल छोड़ दिए हैं।

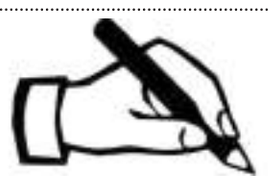
संगठन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण कारोबारी सीजन के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही, माल की आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ना चिंता का विषय है। डीवीएम ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के थोक बाजार केवल राजधानी की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि देशभर के लाखों छोटे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और आपूर्ति शृंखला से जुड़े कारोबारियों की आजीविका का आधार हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा का प्रभाव दिल्ली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है।

महासंघ ने कहा कि रैली के कारण कारोबारी मौसम के महत्वपूर्ण दिनों में बाजारों की सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुईं। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले छोटे व्यापारियों की खरीदारी और व्यापारिक योजनाओं पर असर पड़ा। साथ ही दुकानदारों, कर्मचारियों, मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और उनसे जुड़े परिवारों की आय भी प्रभावित हुई। संगठन ने आगे बताया कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों की सामान्य कारोबारी व्यवस्था और उनकी व्यापारिक छवि को भी झटका लगा। इसके अलावा, ग्राहकों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य व्यापारिक केंद्रों की ओर रुख करने की संभावना भी बढ़ी, जो लंबे समय में स्थानीय कारोबार के लिए चुनौती बन सकती है।

संगठन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण कारोबारी सीजन के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही, माल की आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ना चिंता का विषय है

हालांकि डीवीएम ने यह भी माना कि इस पूरे घटनाक्रम का एक सकारात्मक पक्ष भी सामने आया। संगठन के मुताबिक, दिल्ली के व्यापारिक समुदाय की समस्याओं और चिंताओं को व्यापक सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने का अवसर मिला। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति व्यवस्था में दिल्ली के थोक बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका एक बार फिर प्रमुखता से सामने आई। महासंघ का कहना है कि इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में बड़े राजनीतिक या सार्वजनिक आयोजनों की योजना बनाते समय व्यापारिक हितों, जनसुविधाओं और यातायात प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

सम्पादकीय



दीपावली पर घर वापसी का सफर आसान बनाएगा रेलवे

दीपावली भारत के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर देशभर में रहने वाले लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है और नियमित ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा दीपावली के अवसर पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता है, ताकि त्योहार के दौरान लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी हो।

भारतीय रेलवे की यह पहल त्योहार के मौसम में लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आती है। विशेष ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जयपुर और देश के अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इन ट्रेनों का संचालन यात्रियों की मांग और भीड़ वाले रेल मार्गों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त फेरे लगाए जाते हैं, जबकि कुछ मार्गों पर नई विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं।

त्योहारों के दौरान रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ भीड़ का बेहतर प्रबंधन करना होता है। विशेष ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती भी बढ़ाई जाती है।

दीपावली के अवसर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या विशेष रूप से बढ़ जाती है। रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में विशेष ट्रेनों का संचालन उनके लिए काफी उपयोगी साबित होता है।

हालांकि, त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे के सामने कई चुनौतियां भी रहती हैं। समय पर ट्रेनों का संचालन, टिकटों की उपलब्धता, प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रेलवे को चाहिए कि वह विशेष ट्रेनों की जानकारी समय रहते सार्वजनिक करे, ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकें। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रेलवे की आधिकारिक सूचना प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए। यात्रियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं और रेलवे की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। त्योहार खुशियों और आपसी प्रेम का प्रतीक है, इसलिए यात्रा के दौरान धैर्य और सहयोग बनाए रखना भी आवश्यक है।

खड़गे का 'जन-महाभियोग' : लोकतंत्र की चिंता या राजनीतिक दबाव की नई रणनीति?

सौरभ वार्ष्णेय

लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा को बनाए रखना भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन-महाभियोग जैसा अभियान चलाना कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर और असाधारण परिस्थिति का संकेत है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक असहमति को इस स्तर तक ले जाना उचित है और क्या इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास मजबूत होगा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग प्रस्ताव कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की चुनाव आयुक्त से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है तथा देश में मताधिकार की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। इन आरोपों के बीच उन्होंने विपक्ष की ओर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया। निश्चित रूप से चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता पर सवाल उठना गंभीर विषय है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का परीक्षण करना आवश्यक है।भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की राजनीतिक इच्छा और संवैधानिक अधिकारों की अभिव्यक्ति हैं। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने सौंपी है। इसलिए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना अस्वाभाविक नहीं है।

विपक्ष को यह अधिकार है कि वह चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, पक्षपात या मतदाता अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक मंचों से लगातार आरोप लगाने और जन-महाभियोग जैसी पहल करने से समस्या का समाधान निकल सकता है? महाभियोग की अवधारणा अपने आप में अत्यंत गंभीर है। यह किसी राजनीतिक असहमति का सामान्य हथियार नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया भी संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक होती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के खिलाफ जन-महाभियोग का राजनीतिक अभियान चलाना और वास्तविक संवैधानिक महाभियोग की प्रक्रिया अलग-अलग बातें हैं। जनता के बीच विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसे संवैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं माना जा सकता।

यह भी समझना होगा कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाना कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। इससे देश और विदेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। यदि चुनाव आयोग वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता कर रहा है तो उसके प्रमाण सार्वजनिक किए जाने चाहिए। चुनावी आंकड़ों, मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर ठोस सवाल उठाए जाने चाहिए। विपक्ष को संसद, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक मंचों का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल राजनीतिक भाषणों और आरोपों से किसी संस्था की निष्पक्षता प्रमाणित या खारिज नहीं की जा सकती।

दूसरी ओर, सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष की हर आलोचना को राजनीतिक हताशा बताकर खारिज न करे। लोकतंत्र में विपक्ष केवल चुनाव लडने और सरकार बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि वह सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है तो सरकार और आयोग को तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए।

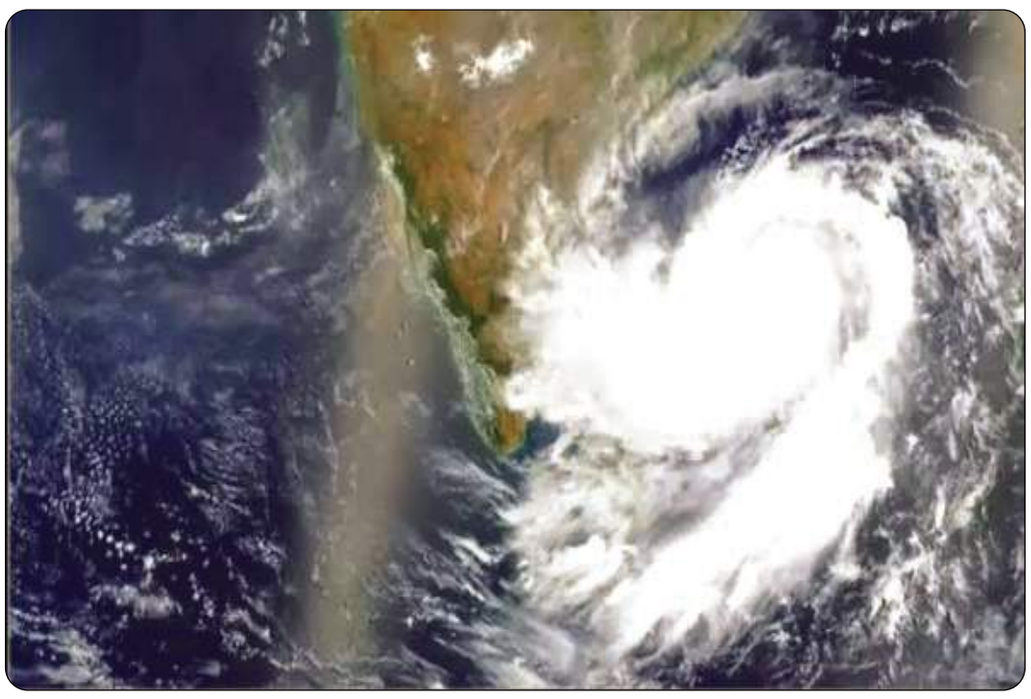
चक्रवातों के साये में तटीय भारत का भविष्य

डॉ. प्रियंका सौरभ

समुद्र जितना जीवनदायी है, उसका रौद्र रूप उतना ही विनाशकारी हो सकता है। भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए बेहद अहम है। लेकिन यही तटीय क्षेत्र हर साल चक्रवातों, समुद्री तूफानों, बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा भी झेलते हैं। चक्रवात अर्नब ने एक बार फिर तटीय भारत की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि चक्रवात कब और कहां आएगा, बल्कि यह भी है कि उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। बदलते मौसम के दौर में अब आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने के बजाय पहले से नुकसान कम करने की रणनीति बनानी होगी।

चक्रवातों से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती उनके बदलते स्वरूप और तीव्रता का अनुमान लगाना है। आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान में सुधार के बावजूद कई बार चक्रवात कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जुटाने के लिए बहुत कम समय बचता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें और नदियों में बाढ़ एक साथ तबाही मचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है।

तटीय क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढांचा भी बड़ी समस्या है। चक्रवात के दौरान बिजली के खंभे गिर जाते हैं, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और संचार सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। इससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित होते हैं। कई तटीय शहरों में अनियोजित निर्माण, जल निकासी की खराब व्यवस्था और निचले इलाकों में बस्तियों का विस्तार खतरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को बचाने के साथ-साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली पहले से बेहतर हुई है, लेकिन चुनौती अब भी यह है कि चेतावनी समय पर हर व्यक्ति तक पहुंचे। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों, दूरदराज के गांवों और छोटे द्वीपों में रहने वाले लोगों तक सूचना पहुंचाना आसान नहीं है। कई बार लोग चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते या घर और आजीविका छोड़ने के डर से सुरक्षित स्थानों पर जाने में देरी करते हैं। इसलिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को उसके खतरे और उससे बचने के उपायों के बारे में समझाना भी जरूरी है।



चक्रवात का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती, मछली पकड़ने या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना भी आसान नहीं होता। उन्हें अपनी संपत्ति, पशुओं और रोजगार की चिंता सताती है।

चक्रवात के बाद मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है, खेतों में खारा पानी भर जाता है और छोटे कारोबार ठप पड़ जाते हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहता है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कमजोर होना भी चिंता का विषय है। मैंग्रोव वनों की कटाई, आर्द्रभूमियों का विनाश और समुद्र तटों पर बढ़ता निर्माण चक्रवातों के खतरे को बढ़ाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री लहरों की ताकत कम करने और तटीय इलाकों को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास भविष्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना होगा। मौसम विभाग की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ उपग्रहों, डॉप्लर रडार और समुद्री निगरानी तंत्र का विस्तार जरूरी है। चेतावनी केवल मोबाइल संदेशों तक सीमित न रहे। सायरन, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय प्रशासन और पंचायतों के माध्यम से भी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। चेतावनी स्थानीय भाषा में हो और उसमें यह साफ बताया जाए कि लोगों को क्या करना है और कहां जाना है।

इसके साथ ही तटीय इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। चक्रवात आश्रयस्थलों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षित निकासी मार्ग बनाने और अस्पतालों, बिजलीघरों तथा पेयजल व्यवस्था को आपदा के लिहाज से मजबूत करने की जरूरत है। आश्रयस्थलों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नियमित मॉक ड्रिल से लोगों को आपदा के समय सही कदम उठाने का अभ्यास कराया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, मछुआरा समितियों और युवाओं को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूलों में आपदा संबंधी जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए। स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के जोखिम की बेहतर जानकारी होती है। इसलिए उनकी भागीदारी से राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनाए जा सकते हैं।

प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर भी नुकसान कम किया जा सकता है। मैंग्रोव वनों, आर्द्रभूमियों और तटीय वनस्पतियों का संरक्षण किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगे और तटीय विनियमन के नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा मछुआरों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए बीमा, आर्थिक सहायता और आजीविका पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है, ताकि आपदा के बाद वे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चक्रवात अर्नब ने यह समझने का अवसर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं, लेकिन बेहतर तैयारी से उनके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। भारत ने मौसम पूर्वानुमान और लोगों की निकासी के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब जरूरत राहत और बचाव तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जो आपदा से पहले ही नुकसान को कम कर सके। आखिरकार, सुरक्षित तट केवल मजबूत इमारतों से नहीं बनते, बल्कि जागरूक नागरिकों, जवाबदेह प्रशासन और संरक्षित पर्यावरण से बनते हैं।

सूरत में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल आखिर कब टूटेगा

कांतिलाल मांडोत

चिकित्सा का पेशा केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि मानव जीवन बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में ऐसे लोगों की संख्या लगातार सामने आ रही है, जिनके पास मान्य मेडिकल डिग्री नहीं है, लेकिन वे बाकायदा डॉक्टर बनकर क्लीनिक चला रहे हैं। मरीजों को दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और बीमारियों का उपचार करते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लगातार छापेमारी ने इस अवैध कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे उजागर कर दिया है।

अक्टूबर महीने में सूरत में हुई कार्रवाइयों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 14 अक्टूबर को पांडेसरा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने 16 कथित झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 1.82 लाख रुपये की दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए थे। इससे पहले 16 सितंबर को पांडेसरा में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके यहां से 98,825 रुपये का सामान जब्त हुआ था। वहीं 11 सितंबर को पांडेसरा में दो अन्य कथित फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा गया था। इन दोनों के क्लीनिक से लगभग 47 हजार रुपये का सामान जब्त किए जाने की खबर सामने आई थी। इस प्रकार सितंबर और अक्टूबर में सामने आई इन तीन कार्रवाइयों में ही 26 लोगों को पकड़े जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई थी।

इसके बाद 29 अक्टूबर को डिंडोली में एसओजी और जिला स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नौ कथित झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ा। इनके पास से 95,138 रुपये की दवाइयां, इंजेक्शन, सिरप और मेडिकल उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने कार्रवाई से पहले डमी मरीज भेजकर क्लीनिकों की जांच भी करवाई थी। जांच में सामने आया कि कुछ लोग दसवीं और बारहवीं पास थे, तो कुछ के पास सामान्य स्नातक की डिग्री थी। कुछ लोग पहले अस्पतालों में कंपाउंडर या सहायक के रूप में काम कर चुके थे।

30 अक्टूबर को सचिन जीआईडीसी में चार क्लीनिकों पर छापेमारी हुई। रामबहादुर वर्मा, आशीष मौर्य, नरोत्तम बैरागी और महेंद्र पंवार को पकड़ा गया। इन चारों के पास एलोपैथी चिकित्सा करने की मान्य डिग्री नहीं थी। पुलिस ने 47,455 रुपये का सामान जब्त किया। इसी दौरान सचिन क्षेत्र में तीन अन्य लोगों अरुणक्रांति विश्वास, चंद्रेश कुमार प्रजापति और सुशांत बिश्वास के खिलाफ भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई। उनके क्लीनिकों से 71,220 रुपये का सामान जब्त किया गया। इस प्रकार सितंबर से अक्टूबर तक उपलब्ध अलग-अलग समाचार रिपोर्टों में कुल 33 लोगों की गिरफ्तारी और कार्रवाई का उल्लेख मिलता है। यदि सचिन के इन तीन मामलों को भी अलग कार्रवाई के रूप में जोड़ा जाए तो आंकड़ा 36 तक पहुंचता है। इन आंकड़ों का पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान जरूरी है, ताकि दोहरी गणना की संभावना समाप्त हो सके।

सवाल यह है कि आखिर बिना डिग्री के लोग वर्षों तक क्लीनिक कैसे चलाते रहते हैं? पांडेसरा में पकड़े गए कुछ आरोपी दो से तीन दशक तक कथित रूप से चिकित्सा करते रहे। किसी ने कंपाउंडर का काम किया तो किसी ने अस्पताल में सहायक के रूप में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को डॉक्टर बताकर क्लीनिक शुरू कर दिए। गरीब और प्रवासी मजदूरों की बड़ी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे क्लीनिकों को मरीज भी मिल जाते हैं। कम फीस, नजदीकी स्थान और तत्काल उपचार का भरोसा लोगों को वहां पहुंचा देता है। यही मजबूरी कुछ अपात्र लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाती है।

कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान मौजूद है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 34 के अनुसार राज्य या राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति ही योग्य आधुनिक चिकित्सा चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की कैद अथवा पांच लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1963 की धारा 30 भी अपंजीकृत व्यक्तियों को चिकित्सा करने से रोकती है। इसके तहत पहली बार अपराध सिद्ध होने पर 500 रुपये तक जुर्माने, दूसरी बार छह महीने तक कैद और 500 रुपये तक जुर्माने तथा बाद के अपराधों में दो वर्ष तक कैद और 2,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अलग-अलग कानूनों की प्रयोज्यता मामले के तथ्यों और संबंधित चिकित्सा पद्धति पर निर्भर करती है।

इसके बावजूद झोलाछाप डॉक्टरों का कारोबार समाप्त नहीं हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण गिरफ्तारी और सजा के बीच लंबी कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दोषी साबित करने के लिए अदालत में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मेडिकल अधिकारियों की रिपोर्ट, डिग्री और पंजीकरण का सत्यापन, गवाहों के बयान तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में समय लगता है। कई मामलों में जांच और न्यायिक सुनवाई लंबी खिंच जाती है। दूसरी ओर, पुराने मामलों में कार्रवाई होने के बावजूद आरोपियों की दोबारा गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती। पांडेसरा में पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आना इसी समस्या की ओर संकेत करता है। सूरत प्रशासन को अब केवल छापेमारी और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शहर के पांडेसरा, डिंडोली, सचिन, उधना, लिंबायत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित सभी क्लीनिकों का नियमित सत्यापन होना चाहिए। चिकित्सकों की डिग्री, पंजीकरण और क्लीनिक के संचालन की अनुमति की जांच अनिवार्य होनी चाहिए। पुराने मामलों की समीक्षा कर दोषियों के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाए। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे क्लीनिकों के दोबारा खुलने पर भी नजर रखनी होगी।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आती रहती हैं। यह समस्या किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। लेकिन सूरत जैसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक शहर में इसका बने रहना चिंता का विषय है। गरीब मजदूरों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि उनकी मजबूरी का फायदा कोई अपात्र व्यक्ति न उठा सके।

आखिरकार चिकित्सा के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानून का भय पैदा करना जरूरी है। गिरफ्तारियों के आंकड़े बढ़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

थाली पर बाज़ार का कब्ज़ा, इलाज के नाम पर नया कारोबार

महेंद्र कुमार कुशवाह

भारत की थाली में आया बदलाव केवल खानपान की आदतों का परिवर्तन नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाजार के बढ़ते वर्चस्व की कहानी है। जिस भोजन को कभी शरीर, प्रकृति और ऋतु के बीच संतुलन का माध्यम माना जाता था, वह धीरे-धीरे औद्योगिक उत्पादन और मुनाफे का उत्पाद बन गया। खेतों से सीधे रसोई तक पहुंचने वाले अनाज, दालें, सब्जियां और पारंपरिक खाद्य पदार्थ अब चमकदार पैकेटों, इंस्टेंट फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बाजार ने सुविधा के नाम पर हमारी थाली में जगह बनाई और धीरे-धीरे हमारी भूख तथा पसंद पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।

इसका परिणाम हमारे सामने है। देश एक ऐसे विरोधाभास से गुजर रहा है, जहां करोड़ों लोग कुपोषण और पोषण संबंधी कमियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, फैटी लिवर और हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती बन रही हैं। यह केवल व्यक्तिगत जीवनशैली का संकट नहीं, बल्कि उस खाद्य व्यवस्था का परिणाम भी है जिसमें सस्ता, सुविधाजनक और आक्रामक ढंग से प्रचारित भोजन अक्सर पौष्टिक विकल्पों पर भारी पड़ता है। भारतीय संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर है। दक्षिण एशियाई आबादी में अपेक्षाकृत कम बीएमआई पर भी पेट के आसपास वसा जमा होने और मेटाबॉलिक जोखिम बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी सामान्य दिखने वाला शरीर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप-2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी समस्याओं की गिरफ्त में हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हमारी स्वास्थ्य नीतियां इस बदलते खतरे को उतनी गंभीरता से समझ रही हैं, जितनी जरूरत है?

इसी संकट के बीच जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं ने दुनिया भर में नई उम्मीद और नया बाजार दोनों पैदा किए हैं। ये दवाएं भूख और तृप्ति से जुड़े जैविक संकेतों को प्रभावित करती हैं तथा चिकित्सकीय निगरानी में वजन घटाने में प्रभावी साबित हुई हैं। मोटापे के उपचार में इनकी भूमिका को नकारना वैज्ञानिक उपलब्धियों से आंखें मूंदने जैसा होगा। लेकिन किसी दवा की सफलता को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सफलता मान लेना भी बड़ी भूल है।

भारत जैसे देश में सबसे बड़ा सवाल इन दवाओं की कीमत, पहुंच और दीर्घकालिक उपयोग का है। जब स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा आज भी लोगों की जेब से खर्च होता है, तब महंगी दवाओं पर आधारित मोटापा नियंत्रण का मॉडल कितनी आबादी तक पहुंच पाएगा? क्या यह समाधान उन परिवारों के लिए भी उपलब्ध होगा, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों में खर्च हो जाता है? हम मोटापे को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का बाजार तो विकसित कर रहे हैं, लेकिन मोटापा पैदा करने वाली खाद्य परिस्थितियों को बदलने के लिए उतनी ही इच्छाशक्ति दिखा पा रहे हैं?

एक तरफ खाद्य उद्योग ऐसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर प्रचार करता है जिनमें अतिरिक्त चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा की भूमिका होती है। दूसरी तरफ खराब खानपान से जुड़े बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों का इलाज एक नए व्यावसायिक अवसर में बदल रहा है। यह कहना गलत होगा कि हर मोटापा किसी एक खाद्य पदार्थ या कंपनी के कारण होता है, लेकिन यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि खाद्य वातावरण और आक्रामक विपणन का लोगों की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोटापे को केवल आलस्य, अनुशासनहीनता या कमजोर इच्छाशक्ति का परिणाम बताना समस्या को सुविधाजनक ढंग से व्यक्ति के सिर मढ़ देना है। भोजन की उपलब्धता, उसकी कीमत, विज्ञापन, शहरी जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब बच्चों को आकर्षक पैकेजिंग, कार्टून चरित्रों और विज्ञापनों के माध्यम से कम उम्र से ही जंक फूड की ओर आकर्षित किया जाता है, तब उनकी खानपान संबंधी पसंद को पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परिणाम कैसे माना जा सकता है?

इस संदर्भ में डेनिश वैज्ञानिक लोटे ब्येरे नुडसन की टिप्पणी विशेष रूप से विचारणीय है। जीएलपी-1 विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नुडसन ने मानव शरीर की विकासवादी संरचना और आज के खाद्य वातावरण के बीच बढ़ते अंतर की ओर ध्यान दिलाया था। उनका तर्क था कि मानव शरीर भोजन की कमी और कठिन उपलब्धता वाले वातावरण में विकसित हुआ, जबकि आज उसे हर जगह उपलब्ध अत्यधिक प्रसंस्कृत और स्वाद-उत्तेजक खाद्य पदार्थों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने खाद्य उद्योग की जनस्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी का सवाल भी उठाया। यह टिप्पणी आधुनिक खाद्य अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। फूड साइंटिस्ट श्रीमंत वैभव साठे कहते हैं हमारा शरीर प्राकृतिक चीजें खाने के लिए ही बना है। प्रकृति ने हमें आलू दिया और हम उसे उबालकर खाने की बजाए चिप्स बनाकर खाने लगे। चने की जगह हमने बेसन से सेंव बना ली। जब हम ताज़ा खा सकते हैं तो फिर पैकेटबंद खाना क्यों खा रहे हैं। भारत में इसका जवाब केवल उपभोक्ता जागरूकता अभियानों से नहीं मिलेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की भूमिका केवल उत्पादों के लाइसेंस और नमूनों की जांच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। खाद्य उत्पादों की पोषण संबंधी जानकारी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अतिरिक्त चीनी, नमक और संतृप्त वसा की अधिक मात्रा वाले उत्पादों पर प्रभावी चेतावनी व्यवस्था, बच्चों को लक्षित भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण और स्कूलों में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के प्रचार पर सख्ती समय की मांग है।

सरकार को मोटे अनाज, दालों, मौसमी फल-सब्जियों और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों को केवल प्रचार अभियानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इन्हें आम परिवार की पहुंच में सस्ता और सहज उपलब्ध कराना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूल पोषण कार्यक्रमों में भोजन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी। स्वस्थ भोजन महंगा और अस्वस्थ भोजन सस्ता रहेगा, तो केवल जागरूकता के भाषणों से खानपान की तस्वीर नहीं बदलेगी। नई दवाएं विज्ञान की उपलब्धि हैं और जरूरतमंद मरीजों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन दवा उस व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकती जो बीमारी के जोखिम को लगातार बढ़ा रही है। जीएलपी-1 दवाओं के संभावित दुष्प्रभाव, उपचार की उपयुक्तता और दवा बंद करने के बाद वजन दोबारा बढ़ने की आशंका जैसे पहलुओं पर चिकित्सकीय निगरानी जरूरी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

अयोध्या का दीपोत्सव त्याग, मर्यादा और समर्पण की भावना को विश्वपटल पर कर रहा प्रतिष्ठित : योगी

लखनऊ (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दसवें भव्य एवं दिव्य दीपोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी कर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। 'योगी की पाती' के माध्यम से उन्होंने कहा कि सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम अपने दसवें दीपोत्सव के स्वागत के लिए तैयार है। दीपोत्सव केवल दीप प्रज्वलन का पर्व नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश, निराशा से आशा और सनातन चेतना के पुनर्जागरण के साथ भारत के सांस्कृतिक गौरव का महापर्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन की स्मृति से जुड़ा यह पावन पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता, आशा और मर्यादा का संदेश देता है। दीपक की छोटी-सी लौ यह सिखाती है कि गहन अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण नई आशा का संचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव से हमारा सनातन संबंध केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन-मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 वर्षों तक भरत जी ने राजसुख का त्याग कर प्रभु श्रीराम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर अयोध्या का शासन संचालित किया। यह प्रसंग सिखाता है कि सत्ता का वास्तविक अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि दायित्व है। अयोध्या का दीपोत्सव त्याग, मर्यादा और समर्पण की इसी भावना को विश्वपटल पर प्रतिष्ठित कर रहा है।

योगी ने कहा कि मां सरयू के तट पर सजी दीपमाला और राम की पैड़ी पर प्रज्ज्वलित लाखों दीपों का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाशगंगा स्वयं अयोध्या में उतर आई हो। ड्रोन के माध्यम से आकाशीय प्रस्तुतियां और कलाकारों की सहभागिता इस महोत्सव को अलौकिक भव्यता प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था और जनभागीदारी को विकास की शक्ति बनाकर उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित की है। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि जहां प्रकाश है, वहां सुरक्षा का वास है। जहां सुरक्षा है, वहां निवेश के अवसर हैं और जहां निवेश है, वहां विकास है। विकास से ही रोजगार, सुख और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। यही उत्सवधर्मिता का आधार है। उन्होंने दीपोत्सव को आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम बताते हुए कहा कि इस आयोजन से कुम्हारों, पुष्प विक्रेताओं, होटल व्यवसायियों और स्थानीय व्यापारियों के लिए रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि यदि उनके आस-पड़ोस में कोई वंचित परिवार है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी दीपावली भी रोशन करें। ऐसे परिवारों को दीये, मिठाइयां और नए वस्त्र भेंट कर उनके जीवन में प्रसन्नता का संचार करें। उन्होंने कहा कि यही दीपोत्सव की सच्ची भावना है। योगी ने विशेष रूप से युवाओं से सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने और नकारात्मकता से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को दीपक के प्रकाश की तरह सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही श्री का वास है। साथ ही स्थानीय कारीगरों के दीप और उत्पाद खरीदकर उनके परिश्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने परिवार और मित्रों के साथ अयोध्या आने तथा प्रभु श्रीराम की पावन नगरी में भव्य दीपोत्सव की दिव्य छटा का साक्षी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कामना की कि हर घर में खुशहाली हो, हर मन में सद्भाव हो और सभी के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो।

डबल इंजन सरकार ने दूर किया अंधकार : योगी

सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने इस अंधकार को दूर किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में लाखों दीपों से आलोकित होने वाला भव्य दीपोत्सव आज कुम्हारों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए काम एवं कारोबार के नए अवसर सृजित कर रहा है।

आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाने वालों पर करें सख्त कार्रवाई : योगी

गोरखपुर (एजेंसी)



गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन, सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वस्त किया कि हर समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। जनता दर्शन में कुछ लोगों द्वारा आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर गलत रिपोर्ट लगाए जाने की शिकायत प्रस्तुत करने पर सीएम योगी की कड़ी नाराजगी जताई। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान देकर समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराया जाए। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने समस्या सुनते हुए लोगों को भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जबरन जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश भी दिए कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी।

बिहार : पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़, 17 मामलों का आरोपी गोली लगने से घायल

वैशाली (एजेंसी)



बिहार के वैशाली जिले में रविवार रात पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। सदर थाना क्षेत्र के मरमला चौर में हुई इस घटना में पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात आरोपी राज नंदन कुमार उर्फ छोटू के दाहिने पैर में गोली लग गई। वैशाली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम उसकी तलाश में छापेमारी करने पहुंची थी। घायल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक, छोटू पर करीब 17 संगीन मामले दर्ज हैं और वह समस्तीपुर के चर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस के अनुसार, रविवार रात वैशाली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम मरमला चौर में छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है।

घायल आरोपी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला निवासी चंदेश्वर राय के पुत्र राज नंदन कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, छोटू वैशाली और समस्तीपुर पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। उस पर लूट, आर्म्स एक्ट समेत करीब 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों में संभावित भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, छोटू समस्तीपुर जिले के चर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का मुख्य आरोपी है। वर्ष 2025 में न्यायालय में पेशी के दौरान वह समस्तीपुर कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद से वैशाली पुलिस और एसटीएफ की टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटू रविवार रात अपने गांव के पास मरमला चौर में छिपा है और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। इसके बाद सदर एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार के नेतृत्व में STF और सदर थाना पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देखकर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी शुभांक मिश्रा और सदर एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

यूपी : आजम खां की दोबारा गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का पहला बयान, बोले- उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा

लखनऊ (एजेंसी)



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान साहब के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार उनके साथ अन्याय कर रही है। आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर सपा अध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने कहा कि देश आजादी का जश्न मना रहा था और मुख्यमंत्री विभाजन का उत्सव मना रहे थे। भाजपा ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कभी तिरंगा नहीं लगाया। लोधी समाज एकजुट हो गया तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी लोधी समाज को सम्मान और स्थान देगी। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा का सफाया होना तय है। 2024 के परिणाम से समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन नंबर एक पर पहुंच गया है।

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार 300 करोड़ पेड़ लगाने का दावा कर रही है, लेकिन पेड़ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे उद्घाटन के बाद जगह-जगह टूट गई, उस पर न जाने कितने गड्ढे हो गए।

200 रुपये की रिश्वत का 48 साल पुराना मामला आखिर बंद, पुलिस की नींद ही नहीं खुली

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)



विशेष निगरानी कोर्ट ने बंदूक के लाइसेंस के बदले 200 रुपये रिश्वत मांगने से संबंधित 48 साल पुराने एक केस को पुलिस की ढिलाई और लापरवाही के कारण बंद कर दिया है। करीब पांच दशक बीत जाने के बाद भी अनुसंधान अधिकारी ने अदालत में प्रगति प्रतिवेदन, अंतिम प्रपत्र अथवा आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। पुलिस महकमे और अभियोजन पक्ष की इस लंबी निष्क्रियता व लचर कार्यप्रणाली को देखते हुए अदालत ने आखिरकार इस मामले का निष्पादन कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम वर्ष 1978 का है। पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले अवधेश प्रसाद सिंह ने बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। आवेदन पत्रों के सत्यापन का काम पारू थाने के तत्कालीन थानाप्रभारी बच्चा सिंह को सौंपा गया था। आरोप के मुताबिक, थानाप्रभारी ने लाइसेंस सत्यापन के एवज में आवेदक से 200 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके विरोध में अवधेश प्रसाद सिंह ने आठ जून 1978 को निगरानी में मामला दर्ज कराया था। इस प्रकरण की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी पुलिस निरीक्षक आरके सिंह को दी गई थी। केस दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया बेहद सुस्त बनी रही।

जांच अधिकारी ने लगभग पांच दशक लंबा समय बीतने के बाद भी कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। अदालत विभिन्न तिथियों पर लगातार सुनवाई करती रही और जांच अधिकारी को आरोप पत्र जमा करने के निर्देश देती रही। इसके लिए कई बार स्मरण पत्र भी जारी किए गए। कोर्ट ने अंतिम बार इसी साल नौ अक्तूबर को रिमाइंडर भेजा था। इसके बाद भी पुलिस अधिकारियों की नींद नहीं खुली और न ही जांच पूरी करके अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि केस दर्ज होने के बाद से लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लंबे समय तक पेंडिंग रहने के कारण केस से जुड़े अभिलेख के मुख्य पन्ने जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं, जो अब पढ़ने योग्य भी नहीं रहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली को देखते हुए निकट भविष्य में इस मामले में किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं बची है। तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में यदि संबंधित थाने की ओर से कोई नया साक्ष्य या तथ्य आता है, तो तत्कालीन न्यायालय आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकेगा।

बिहार : पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, रोज 110 दस्तावेजों का डिजिटल निबंधन; क्यूआर कोड से मिलेगी कॉपी

नालंदा (एजेंसी)

बिहार के नालंदा जिले में जमीन की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदल रहा है। कागजी फाइलों और लंबी प्रक्रियाओं की जगह अब डिजिटल व्यवस्था ने ले ली है। पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर शुरुआती दौर में रही झिझक और भ्रांतियां अब कम हो रही हैं। इसका असर निबंधन कार्यालयों के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। जिले में रोजाना करीब 110 जमीनों की खरीद-बिक्री डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही है।

नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के तुरंत बाद खरीदार को दस्तावेज की डिजिटल कॉपी भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिले के बिहारशरीफ निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन औसतन 65 से 70 दस्तावेजों का निबंधन किया जा रहा है। वहीं, हिलसा और राजगीर अनुमंडलीय निबंधन कार्यालयों के आंकड़ों को मिलाकर जिले में रोजाना करीब 110 दस्तावेजों का डिजिटल निबंधन हो रहा है। जिला अवर निबंधक मनीष कुमार के अनुसार, अगस्त 2026 से प्रभावी हुई पेपरलेस व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और आम लोगों का समय बचाना है। पहले कागजी औपचारिकताओं और फाइलों के कारण लोगों को काफी समय देना पड़ता था। अब प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान और तेज हो गई है। रजिस्ट्री पूरी होते ही खरीदार को मूल दस्तावेज सौंप दिया जाता है। नई व्यवस्था में खरीदार के निबंधित मोबाइल नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। इसके साथ ही रजिस्टर्ड डीड की सुरक्षित पीडीएफ कॉपी भी उपलब्ध कराई जाती है। इससे दस्तावेज की डिजिटल प्रति हासिल करने के लिए दोबारा कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिजिटल डीड पर एक सुरक्षित क्यूआर कोड अंकित रहता है।

बिहार : दिवाली और छठ पर पांच तारीख से पांच राज्यों के लिए चलेंगी 200 विशेष बसें, टिकट बुकिंग शुरू

पटना (एजेंसी)



बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिवाली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष त्योहारी बस सेवा के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार 5 से 20 नवंबर के बीच चिह्नित मार्गों पर लगभग 200 विशेष बसों का संचालन करेगी। यह विशेष बस सेवा बिहार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए होगी। निगम ने यात्रियों के आवागमन के लिए एसी सीटर, एसी स्लीपर, सेमी-स्लीपर और नॉन-एसी बसों का इंतजाम किया है।

यात्री निगम की आधिकारिक वेबसाइट https:// bsrtc. bihar. gov.in/ पर जाकर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। परिवहन विभाग पिछले वर्ष की तरह ही त्योहारों के दौरान यात्रियों को किफायती यात्रा का विकल्प दे रहा है। त्योहारों के समय यात्री सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। एसी सीटर एवं स्लीपर बस की टिकट बुकिंग करने पर 30 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी दी जा रही है। त्योहारी भीड़ को देखते हुए बिहार के अलग-अलग प्रमुख शहरों से अन्य राज्यों के लिए बसों का परिचालन निर्धारित किया गया है। पटना से दिल्ली के लिए 13, हरियाणा के लिए सात और झारखंड के लिए चार बसें रवाना होंगी। मुजफ्फरपुर से दिल्ली मार्ग पर 34 बसें चलाई जाएंगी। गया से दिल्ली के लिए 10 बसों की सेवा रहेगी, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए दो-दो तथा झारखंड के लिए छह बसें संचालित होंगी। इसके अलावा पूर्णिया से दिल्ली के लिए 12 और हरियाणा के लिए 18 बसें चलेंगी। दरभंगा से दिल्ली के लिए छह और हरियाणा के लिए 22 बसें संचालित की जाएंगी। इसी तरह अन्य प्रमुख रूटों पर भी बसों का परिचालन किया जाएगा। छूट के बाद बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए किराया तय कर दिया गया है। पटना से दिल्ली नॉन-एसी सीटर का किराया 1182 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर का 1483 रुपये, एसी सीटर का 1318 रुपये और एसी स्लीपर का किराया 1935 रुपये निर्धारित है।

मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए नॉन-एसी सीटर 1074 रुपये, स्लीपर 1352 रुपये, एसी सीटर 1195 रुपये और एसी स्लीपर 1767 रुपये है। गया जी से दिल्ली रूट के लिए नॉन-एसी सीटर 1139 रुपये, स्लीपर 1426 रुपये, एसी सीटर 1272 रुपये और एसी स्लीपर 1861 रुपये तय हुआ है। दरभंगा से दिल्ली के लिए नॉन-एसी सीटर 1165 रुपये, स्लीपर 1461 रुपये, एसी सीटर 1201 रुपये और एसी स्लीपर 1908 रुपये निर्धारित है। पूर्णिया से दिल्ली के लिए नॉन-एसी सीटर 1486 रुपये, स्लीपर 1842 रुपये, एसी सीटर 1668 रुपये तथा एसी स्लीपर 2398 रुपये किराया तय किया गया है।

बिहार : कहां है अविनाश? छह महीने से लापता बेटे की तलाश में परिवार ने लगाई गुहार, इनाम की घोषणा

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के केरमा गांव से छह महीने पहले लापता हुए 16 वर्षीय किशोर अविनाश कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजन उसकी तलाश में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उनका धैर्य भी जवाब देने लगा है। परिवार ने अब अविनाश की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही, उसे ढूंढने या उसके सुरक्षित होने की सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा भी की है।

पूरा परिवार आज भी अविनाश के लौटने का इंतजार कर रहा है। बताया जाता है कि 16 वर्षीय अविनाश रामनवमी मेले के बाद अचानक घर से लापता हो गया था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है। परिजन उसकी तलाश में हर संभव जगह जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन छह महीने बीत जाने के बावजूद सफलता नहीं मिली है। बेटे का पता नहीं चलने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लापता किशोर के पिता झुनझुन राम ने बताया कि अविनाश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज भी चल रहा था। ऐसे में उसके सुरक्षित होने को लेकर परिजन बेहद चिंतित हैं। परिवार ने आम लोगों से भावुक अपील की है कि यदि किसी को भी अविनाश दिखाई दे या उसके संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल दिए गए मोबाइल नंबरों पर सूचना दें। सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को परिजनों की ओर से उचित इनाम दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि छह महीने बीत जाने के बाद भी अविनाश का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण भी उसकी जल्द वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।

हमीरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

हमीरपुर (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी हीरालाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटनास्थल पर छिपाकर रखे गए अवैध देसी तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, एक नवंबर को मुस्करा थाना क्षेत्र के एक कस्बे में तीन साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी हीरालाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी और घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गईं।

पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी ने मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। एएसपी अरविंद कुमार ने बताया, एक नवंबर को मुस्कारा थाना क्षेत्र के कस्बे में तीन साल की एक बच्ची का शव मिला। बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई गईं। टीम ने नामजद आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद जब आरोपी को सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया तो उसने एक अवैध देसी पिस्तौल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त महिला की गैर इरादतन हत्या में आया फैसला, कोर्ट ने आठ आरोपियों को किया दोषमुक्त

मुजफ्फरनगर (एजेंसी)



मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शामली के गांव लांक में बुजुर्ग सकूरन (70) की गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। अलग-अलग दो प्राथमिकी, मेडिकल रिपोर्ट और मृतका को सिर्फ एक चोट और नौ आरोपी बनाए जाने के तथ्य को अभियोजन साबित नहीं कर सका।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी अनुराग पंवार ने फैसला सुनाया। नंगला मंदौड़ पंचायत के बाद सात सितंबर 2013 की रात जिले में दंगा भड़क उठा था। आठ सितंबर को लांक गांव में बुजुर्ग सकूरन के सिर पर वार किया गया। पुलिस सुरक्षा में घायल को पहले शामली और फिर जिला चिकित्सालय में उपचार दिलाया गया था। बाद में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका के बेटे वादी युसूफ सैफी ने 21 अक्तूबर को प्राथमिकी में लांक के वीरेंद्र, विकास, अंकुर, जगपाल, अरविंद, मोहित, अनुज, संदीप और बागपत के सुन्हेड़ा निवासी दीपक को घर पर हमले के मामले में आरोपी बनाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया।

लांक में रिश्तेदारी में रह रहे सुन्हेड़ा निवासी दीपक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। आठ अगस्त 2017 को आरोप तय हुए। अभियोजन ने पांच गवाह पेश किए। आरोप साबित नहीं होने के कारण आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। सकूरन की गैर इरादतन हत्या के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वादी युसूफ सैफी के अलावा दूसरी प्राथमिकी कैराना राहत शिविर में साजिद की ओर से दी गई। दोनों की एक साथ जांच हुई, जिसमें तथ्य अलग मिले। 21 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज हुई और कैराना में 22 अक्तूबर को पंचायतनामा भरा गया था। जांच में सामने आया कि घायल हालत में सकूरन को नौ सितंबर को जिला अस्पताल लाया गया, यहां 10 अक्तूबर को डॉक्टरों ने जांच की। परिजनों ने 12 सितंबर को अपनी मर्जी से रेफर करा लिया था।

शामली जनपद के लांक गांव में बुजुर्ग महिला सकूरन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज किया था। नंगला मंदौड़ पंचायत के बाद वारदात की गई थी

इसके बाद की मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली और 21 अक्तूबर को कैराना में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। वादी और उसकी पत्नी ने भी प्रत्यक्षदर्शी होने से इन्कार कर दिया। पंचनामे में मृतका की दाहिनी आंख के ऊपर सिर पर केवल एक चोट आना अंकित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका के सिर पर केवल एक चोट आना दर्शित किया गया है।

क्वाड का आर्थिक सुरक्षा पर जोर, महत्वपूर्ण खनिजों और एआई में सहयोग बढ़ाएंगे भारत समेत चारों देश

अमेरिका के अटलांटा में 31 अक्टूबर को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। जिसमें आर्थिक सुरक्षा को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी बताया गया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए

वाशिंगटन (एजेंसी)



इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), समुद्री सुरक्षा और डिजिटल संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। चारों देशों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और बाजार को विकृत करने वाली नीतियों पर चिंता जताई है।

अमेरिका के अटलांटा में 31 अक्टूबर को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। जिसमें आर्थिक सुरक्षा को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी बताया गया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार, चारों देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता दोहराते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण उद्योगों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन, गैर-बाजार नीतियां और मनमाने निर्यात प्रतिबंध वैश्विक व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

क्वाड के महत्वपूर्ण खनिज पहल ढांचे के तहत चारों देश इलेक्ट्रॉनिक कचरे और कबाड़ से महत्वपूर्ण खनिजों को दोबारा हासिल करने, प्रसंस्करण संयंत्रों और रिफाइनरियों के विकास तथा वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम करेंगे। अमेरिका ने 'भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने वाली सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक करोड़ डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।' इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों में इन खनिजों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए यह सहयोग आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से अहम है। एआई के क्षेत्र में भी क्वाड ने बड़ी पहल की घोषणा की है। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद एआई तकनीक तक पहुंच बढ़ाने के लिए आठ करोड़ 50 लाख डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का इरादा रखते हैं। इसके लिए क्वाड एसआई एक्सेलेरेटर के माध्यम से काम किया जाएगा।

विज्ञप्ति में 'एसआई' यानी 'सुपर इंटेलिजेंस' का उल्लेख किया गया है, जिसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। बैठक में समुद्री सुरक्षा को भी आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा गया। चारों देशों ने होर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (यूएनसीएलओएस) (सामान्य भाषा में समुद्र का कानून या समुद्र का संविधान) के अनुरूप समुद्री मार्गों पर बगैर व्यवधान के आवागमन और जहाजों पर किसी भी प्रकार का टोल नहीं लगाए जाने की बात कही। भारत की समुद्री भूमिका के लिहाज से चेन्नई से पर्थ तक हुई क्वाड की दूसरी समुद्री पर्यवेक्षक यात्रा भी महत्वपूर्ण रही। यह यात्रा 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भारतीय तटरक्षक बल के एक अपतटीय गश्ती पोत पर आयोजित की गई, जिसमें चारों देशों के प्रतिनिधि सवार थे। इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी और अवैध गतिविधियों से निपटने में आपसी तालमेल बढ़ाना है। चारों देश 2027 में सी ड्रैगन अभ्यास के दौरान हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल के तहत अपना पहला संयुक्त अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के करीब 75 फीसदी लोगों ने माना, 'एक साल में देश और बंटा'

सिडनी (एजेंसी)



ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की खाई बढ़ती जा रही है। एक नए सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। करीब तीन-चौथाई नागरिकों ने माना कि उनका देश पिछले एक साल में पहले के मुकाबले अधिक बंट गया है। इसके साथ ही सरकार, राजनीतिक दलों और नेताओं पर जनता का भरोसा भी कमजोर हुआ है। स्वतंत्र थिंक टैंक मैकिनॉन की ने ये सर्वे कराया।

सर्वेक्षण में 41.9 प्रतिशत लोगों ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 12 महीनों में अधिक विभाजित हुआ है, जबकि 32.5 प्रतिशत ने इससे कुछ हद तक सहमति जताई। इस तरह कुल 74.4 प्रतिशत लोगों ने देश में बढ़ते विभाजन को महसूस किया। सर्वेक्षण के मुताबिक, देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर संतुष्ट लोगों की संख्या भी घटी है। वर्ष 2025 में 28.8 प्रतिशत लोगों ने खुद को बहुत या कुछ हद तक संतुष्ट बताया था, लेकिन 2026 में यह आंकड़ा घटकर 26.1 प्रतिशत रह गया। वहीं, देश की दिशा को लेकर पूरी तरह असंतुष्ट लोगों की संख्या में 7.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जून और जुलाई में हुए इस सर्वेक्षण में 4,000 से अधिक लोगों से ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था, नेताओं और संस्थानों को लेकर उनकी राय पूछी गई। सर्वेक्षण में संघीय नेताओं और राजनीतिक दलों पर भरोसे में गिरावट भी सामने आई। वर्ष 2025 में 35.9 प्रतिशत लोगों ने संघीय राजनेताओं पर पूरा भरोसा जताया था, जो 2026 में घटकर 30.5 प्रतिशत रह गया। राजनीतिक दलों पर पूरा भरोसा रखने वालों का अनुपात भी 31.2 प्रतिशत से गिरकर 24.4 प्रतिशत पर आ गया। मैकिनॉन के अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष और विक्टोरिया राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री जॉन थ्वेट्स ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा उस राजनीति के मुकाबले कहीं अधिक है, जो इन संस्थाओं के भीतर संचालित होती है।

'नियमों का उल्लंघन' करने वाले तेल टैंकरों में विस्फोट, बारूदी सुरंग से टकराए थे दोनों : ईरान

तेहरान (एजेंसी)



ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पिछले कुछ घंटों के दौरान दो 'नियम उल्लंघन करने वाले' सुपरटैंकर समेत एक तेल टैंकर में धमाका हुआ। कथित तौर पर ये दोनों बारूदी सुरंगों (नेवल माइन्स) से टकराए जिससे विस्फोट हुआ और दोनों वहीं रुक गए। रविवार (स्थानीय समय) को आईआरजीसी के आधिकारिक समाचार आउटलेट 'सिपाह न्यूज' पर जारी एक बयान में, नौसेना ने कहा कि ये टैंकर जलडमरूमध्य में एक 'अनधिकृत' (बिना अनुमति वाले) रास्ते से गुजर रहे थे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इसमें आगे कहा गया कि सुपरटैंकर में 'एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह धू-धू कर जल रहा है।' बताया गया कि दोनों जहाजों ने अपने नेविगेशन और पहचान प्रणालियों (आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) को बंद कर रखा था। ईरान ने 28 फरवरी को इस स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी।

उसने इजरायल और अमेरिका के जहाजों–या उनसे जुड़े जहाजों - के सुरक्षित आवागमन पर रोक लगा दी थी। यह कदम ईरानी क्षेत्र पर उनके संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया था। इससे पहले, आईआरजीसी के प्रवक्ता होसैन मोहेब्बी ने कहा कि ईरानी बलों ने 'दुश्मन' को नुकसान पहुंचाने और रोकने के लिए एक विशाल युद्धक्षेत्र तय कर लिया है। अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के हवाले से सिन्हुआ ने बताया कि रविवार (स्थानीय समय) को ईरान के दक्षिण-पूर्वी केरमान प्रांत में एक सम्मेलन में मोहेब्बी ने कहा कि ईरानी बल 'दुश्मन को निर्णायक जवाब देने के लिए' पहले से कहीं अधिक तत्पर हैं। उन्होंने सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई द्वारा वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को दिए गए हालिया आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर के इन निर्देशों ने 'युद्ध का एक नया अध्याय' शुरू कर दिया है। मोहेब्बी ने खामेनेई की उस बात का उल्लेख खासतौर पर किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के साथ युद्ध में कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।

अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बड़ी दस्तक, 57 चेहरे मंगलवार को आजमाएंगे किस्मत

वाशिंगटन (एजेंसी)



अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में इस बार भारतीय मूल के उम्मीदवारों की उल्लेखनीय मौजूदगी देखने को मिल रही है। ओहायो में गवर्नर पद से लेकर लॉस एंजिलिस के मेयर और मैसाचुसेट्स की सीनेट सीट तक, भारतीय मूल के 57 उम्मीदवार मंगलवार को मतदाताओं के बीच अपनी किस्मत आजमाएंगे।

यह संख्या अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित करती है। देशभर से जुटाई एक लिस्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इन 57 उम्मीदवारों में एक सीनेट, 11 प्रतिनिधि सभा, तीन राज्यव्यापी पदों, 36 राज्य विधानमंडलों और छह स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सूची में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिनकी भारतीय मूल की पहचान की पुष्टि हो सकी है। इसके अलावा 15 ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं, जिन्हें भारतीय मूल का माना जा रहा है, लेकिन पर्याप्त पुष्टि नहीं होने के कारण सूची में जगह नहीं मिली है। इन चुनावों में सबसे अधिक निगाहें ओहायो पर रहेंगी, जहां रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी गवर्नर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन को चुनौती दे रहे हैं। रविवार को उपलब्ध फिफ्टीप्लसवन के पोलिंग औसत में एक्टन को करीब तीन अंकों की बढ़त दिखाई गई। रामास्वामी की उम्मीदवारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और उनकी जीत अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की स्थिति को एक नई ऊंचाई दे सकती है। लॉस एंजिलिस में सिटी काउंसिल सदस्य नित्या रमन मौजूदा मेयर करेन बास को चुनौती दे रही हैं। यूसी बर्कले इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंटल स्टडीज और लॉस एंजिलिस टाइम्स के संयुक्त सर्वेक्षण में दोनों उम्मीदवारों को 40-40 प्रतिशत समर्थन मिला, जबकि 19 प्रतिशत मतदाता अब भी अनिर्णीत थे। यह मुकाबला भी भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बढ़ती राजनीतिक पहुंच का एक अहम उदाहरण है। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन उम्मीदवार सरिता कोमाटिरेड्डी अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ मैदान में हैं।

28 अक्टूबर को जारी सिएना सर्वेक्षण में जेम्स को 54 प्रतिशत और कोमाटिरेड्डी को 39 प्रतिशत समर्थन मिला था। मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर भी दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वह गवर्नर पद के उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में हैं, जबकि रिपब्लिकन टिकट में डैन कॉक्स शामिल हैं।

यमुनानगर में बाल-बाल बचे एसडीएम, डंपर ड्राइवर ने कुचलने की कोशिश की थी

यमुनानगर (एजेंसी)

हरियाणा के यमुनानगर जिले में पुलिस ने अवैध माइनिंग में शामिल एक डंपर के ड्राइवर के खिलाफ व्यासपुर के एसडीएम को कुचलने की कोशिश के मामले में केस दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस के मुताबिक, व्यासपुर के एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह ने 31 अक्टूबर की सुबह हुई इस घटना के बारे में सधौरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में एसडीएम ने कहा कि वह सुबह करीब 6.15 बजे 'रन फॉर यूनिटी' प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सधौरा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जा रहे थे, तभी उन्होंने रेस्ट हाउस के पास एक डंपर ट्रक देखा।

डंपर की नंबर प्लेट धुंधली थी, और एसडीएम को शक था कि उसमें गैर-कानूनी तरीके से माइन का सामान ले जाया जा रहा है। उन्होंने ड्राइवर को इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी रोकने का इशारा किया। लेकिन, ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी तेज कर दी और एसडीएम को कुचलने के इरादे से सीधे उनकी ओर डंपर ले जाने की कोशिश की। डॉ. सिंह बाल-बाल बच गए और गाड़ी का पीछा करने से पहले तुरंत पुलिस को बताया। पीछा करते समय, एक सफेद कार, जो डंपर का पीछा कर रही थी, ने एसडीएम की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि कार ड्राइवर ने जानबूझकर गलत तरीके से गाड़ी चलाई और अचानक ब्रेक लगाकर एसडीएम का रास्ता रोका, जिससे डंपर ड्राइवर मौके से भाग गया। एसडीएम ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। सढौरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज लखविंदर सिंह ने कहा कि एसडीएम की शिकायत के आधार पर डंपर ड्राइवर और कार में बैठे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, और पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है।

सौरभ चंद्राकर प्रत्यर्पण मामले में सीएम विष्णु देव साय ने सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को दी बधाई

रायपुर (एजेंसी)



महादेव सट्टेबाजी स्कैम केस और मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के ओमान से दिल्ली प्रत्यर्पण और उसके बाद रायपुर ट्रांसफर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, 'महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को देश में लाया जाए, इसको लेकर सीबीआई का प्रयास था। अब इस मामले में सभी जानकारियां मिलेंगी।

यह बड़ी सफलता है। इसको लेकर सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को बहुत-बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रविवार को कहा था, सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट के आरोपी सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक करवा लिया है, साथ ही कहा कि पूछताछ से अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महादेव ऐप के अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर और मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। सीबीआई की एक विशेष टीम उसे ओमान से भारत लेकर आई है। अब उसे रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सौरभ चंद्राकर दो सीबीआई मामलों में वांछित है, जिनमें पहले ही आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में भी उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की जा चुकी है। यह प्रत्यर्पण भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे विदेशों में बैठकर भारतीय नागरिकों के खिलाफ अपराध करने वाले भगोड़ों को वापस लाकर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई करने के प्रयासों को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मामलों की जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था, जिसे भारत के बाहर से संचालित किया जाता था। यह नेटवर्क क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर अवैध सट्टेबाजी कराता था। इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी-आधारित 'पैनल' और 'ब्रांच' का नेटवर्क बनाया गया था, जो लोगों को जोड़ने और उनसे पैसे लेने का काम करता था। जांच में यह भी पता चला कि अवैध सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को बड़ी संख्या में फर्जी बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता था। कई स्तरों के लेनदेन के बाद इस रकम को हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था।

झारखंड : कथित दुष्कर्म मामले में 15 पुलिसकर्मी निलंबित, 3 गिरफ्तार

रांची (एजेंसी)

झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया पुलिस स्टेशन परिसर में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में कम से कम 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज स्वर्गियारी ने रविवार को दो सब-इंस्पेक्टर, चार सहायक सब-इंस्पेक्टर, दो हवलदार और एक कांस्टेबल सहित नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

इससे पहले, एक किशोरी के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सहित छह पुलिसकर्मियों को सेवा से निलंबित किया गया था। कुल मिलाकर, पुलिस स्टेशन के अंदर महिला के साथ घोर दुर्व्यवहार और यौन दुराचार के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में आरोपी– वायरलेस ऑपरेटर नीरज लकरा, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी (ओडी), और स्टेशन क्लर्क (मुंशी) शामिल हैं। तीनों को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी मनोज स्वार्गियारी ने मामले की जांच के लिए रविवार को गम्हरिया पुलिस स्टेशन का दौरा किया। नौ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना समय पर न देने के कारण की गई है।

पुलिस के अनुसार, गम्हरिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दुग्धा गांव की निवासी महिला गुरुवार देर रात पारिवारिक विवाद और पति द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए स्टेशन पहुंची। देर रात होने के कारण उसे स्टेशन में ही रुकने की सलाह दी गई। आरोप है कि इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात वायरलेस ऑपरेटर नीरज लकरा महिला को पुलिस स्टेशन परिसर के एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

देहरादून जेल पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य, महिला बंदियों की सुविधाओं की समीक्षा

देहरादून (एजेंसी)



राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सदस्य निवेदिता सुब्रमणियन ने रविवार को उत्तराखंड के देहरादून स्थित जिला जेल का निरीक्षण किया और कैदियों के पुनर्वास पर जोर दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सुब्रमणियन ने सुविधाओं का निरीक्षण किया और महिला कैदियों की जीवन स्थितियों का आकलन किया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर उनकी चिंताओं, जरूरतों और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया, जिसमें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण और गरिमापूर्ण जीवन स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया। बयान में कहा गया है कि इस दौरे के दौरान, एनसीडब्ल्यू सदस्य ने पुनर्वास, कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण के अवसरों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। शनिवार को, एनसीडब्ल्यू ने महिला कैदियों के अधिकारों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए देहरादून में एक अखिल भारतीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। बयान में कहा गया है कि बैठक में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल महानिदेशकों (डीजी जेल) और वरिष्ठ जेल अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक की अध्यक्षता एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने की। इस परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य आयोग द्वारा विभिन्न परामर्श बैठकों के आधार पर केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना विकसित करना था। ये सिफारिशें महिला कैदियों के अधिकारों, जेलों में उनकी स्थितियों और उनके पुनर्वास से संबंधित थीं। बयान में यह कहा गया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सुब्रमणियन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में जेलों में महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बयान में कहा गया है कि मौजूदा प्रणालियों में कमियों की पहचान करने और महिला कैदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया है कि महिला कैदियों के लिए स्त्री रोग और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

उज्जैन : भस्म आरती में बाबा महाकाल का भांग-चंद्रमा और ड्रायफ्रूट से सजा स्वरूप, जयकारों से गूंजा मंदिर

उज्जैन (एजेंसी)



विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार की सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया।

इस दौरान भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत को अर्पित कर किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई। सोमवार के श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि आज बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार कर चन्द्रमा और बेलपत्र अर्पित किए गए। बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगे। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं।

आम आदमी पार्टी हरमीत सिंह और चेतन सिंह की सदस्यता रद्द करने की स्पीकर से करेगी मांग

चंडीगढ़ (एजेंसी)

पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आम आदमी पार्टी ने अपने दो विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आम आदमी पार्टी विधानसभा स्पीकर से उनकी सदस्यता भी रद्द करने की मांग करेगी। दोनों विधायकों ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन पंजाब के पटियाला जिले की दो विधानसभा सीटों से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, पार्टी ने कहा था कि इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत निकाला गया है। सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह पंजाब विधानसभा में सनौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। बताया जा रहा है कि उनकी अपनी ही सरकार ने



विधायक पठानमाजरा के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ तीखे तेवर अपना लिए थे और अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं, समाना से विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था।

बताया जा रहा है कि हाल ही में आई आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। चेतन सिंह जोड़ामाजरा साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर समाना से भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वे भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब 'आप' प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा था, आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब को प्राथमिकता दी है। अगर हमारे किसी नेता ने कभी भ्रष्टाचार किया या पंजाब के हितों के खिलाफ काम करने की कोशिश की तो हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। पंजाब 'आप' प्रदेश अध्यक्ष ने आगे लिखा था, अब भाजपा इन्हीं निकाले गए लोगों को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि उसका अपना कोई आधार नहीं है और उसे पंजाब के हितों की कोई परवाह नहीं है। जो व्यक्ति पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाकर भाग गया हो, और जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा हो, वह पंजाब का क्या भला करेगा? लेकिन भाजपा को ठीक ऐसे ही लोग चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित : इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान

पर्थ (एजेंसी)



ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू सफेद गेंद की सीरीज के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। 13 नवंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के मद्देनजर तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को इस सीरीज से विश्राम दिया गया है।

यह रोमांचक सीरीज 13 नवंबर को पर्थ में वनडे मुकाबले के साथ शुरू होगी, जिसके बाद 15 और 18 नवंबर को क्रमशः एडिलेड और होबार्ट में दूसरे और तीसरे मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टी20 फॉर्मेट की शुरुआत 21 नवंबर को मेलबर्न से होगी। बाकी के चार टी20 मुकाबले गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा में खेले जाएंगे और सीरीज का आखिरी मुकाबला दो दिसंबर को होगा।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सितंबर में खेली गई सीरीज के दौरान साइड स्ट्रेन (पसली की चोट) से उबर रहे तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी वनडे सीरीज के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में चयनकर्ताओं ने कई युवा और नए चेहरों पर भरोसा जताया है। 14 सदस्यीय वनडे टीम में पूर्व अंडर-19 विश्व कप खिलाड़ी महली बियर्डमैन और ओलिवर पीक को शामिल किया गया है, जबकि जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट को भी मौका मिला है। इसके अलावा, टी20 टीम में निखिल चौधरी, जोएल डेविस, लछलन शॉ और सैम हार्पर जैसे नए चेहरे शामिल किए गए हैं।

टीम को लेकर क्या बोले चयन समिति के अध्यक्ष बेली

टी20 सीरीज के दौरान कुछ नियमित खिलाड़ी भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि टेस्ट नियमित खिलाड़ी ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस और कूपर कॉनली वनडे सीरीज खेलने के बाद टी20 मुकाबलों से बाहर रहेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, ये वनडे और टी20 मैच कई खिलाड़ियों को, जिनमें से कई को हालिया दौरों पर मौके मिले हैं, बहुत मजबूत विपक्ष के खिलाफ अपनी क्षमता को और साबित करने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। लियाम स्कॉट वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं और हम इस बात से उत्साहित हैं कि वह हर मौके से सीखते हैं और पिछले 12-18 महीनों में मजबूत प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपने खेल को आगे बढ़ाया है। महली बियर्डमैन का ऑस्ट्रेलिया ए के लिए हालिया प्रदर्शन प्रभावशाली था, और हम वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमें लगता है कि वह आने वाले वर्षों में सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी के रूप में विकसित हो सकते हैं।

बेली ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, लची शॉ एक बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे तेजी से विकसित होंगे और उनके पास एक ऐसा दमदार खेल है जो टी20 फॉर्मेट में प्रभाव डालेगा। सैम हार्पर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। वह इस समय अपने खेल के मामले में एक बेहतरीन स्थिति में हैं और सभी फॉर्मेट में अपने खेल की शैली को लगातार बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे हैं।

जेक (फ्रेज़र-मैकगर्क) और मिच (ओवेन) की टी20 टीम में वापसी हुई है, और हमें विश्वास है कि उनकी गेंद को हिट करने की क्षमता छोटे फॉर्मेट में एक अलग अंतर पैदा कर सकती है। वे ऐसे खिलाड़ियों के अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलने पर उन अनुभवों से सीखकर अपने खेल पर काम करना जारी रखा है।

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम : मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, एडम जैम्पा।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम : मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, टिम डेविड, जोएल डेविस, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, सैम हार्पर, स्पेंसर जॉनसन, मिच ओवेन, लछलन शॉ, एडम जैम्पा।

मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती मेक्सिको सिटी जीपी, एंटोनेली बने युवा एफ-1 चैंपियन

मेक्सिको सिटी (एजेंसी)



किमी एंटोनेली अब तक के सबसे युवा फॉर्मूला-1 वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में तीसरे स्थान पर रहने के साथ ही मर्सिडीज के इस ड्राइवर ने 2026 का खिताब अपने नाम किया। वहीं, इस रेस में मैक्स वेरस्टैपेन ने लुईस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की।

20 साल और 68 दिन की उम्र में एंटोनेली ने सेबेस्टियन वेटेल का रिकॉर्ड तोड़ा। वेटेल ने 2010 में रेड बुल के साथ अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी, तब उनकी उम्र 23 साल और 134 दिन थी। ऑटोड्रोमो हर्मनोस रोड्रिग्ज में हुई 71-लैप की इस रेस में एंटोनेली को अपना पहला एफ-1 खिताब जीतने के लिए केवल नौवें स्थान पर रहने की जरूरत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी लुईस हैमिल्टन और मर्सिडीज के उनके साथी जॉर्ज रसेल किस स्थान पर रहते।

एंटोनेली ने कहा, हमने कर दिखाया और सच कहूं तो उनके बिना मैं यहां नहीं होता। मर्सिडीज और अपने परिवार के बिना यह मुमकिन नहीं था। मैं इस पल के लिए बहुत आभारी हूं, यह एक ऐसा पल है जो हमेशा याद रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। फॉर्मूला-1 की रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्षीय एंटोनेली ने चौथे स्थान से शुरुआत की और अंततः तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा–वाल्टेरी बोटास के भीषण एक्सीडेंट के कारण रेस के बीच में 'रेड फ्लैग' आया, और बाद में अरविद लिंडब्लाड के क्रैश होने के कारण 'सेफ्टी कार' को मैदान में उतारना पड़ा।

वेरस्टैपेन ने इस सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। उन्होंने फेरारी के लुईस हैमिल्टन को 0.799 सेकंड के अंतर से पीछे छोड़ा। ग्रिड पर पांचवें स्थान से शुरुआत करने वाले रेड बुल के इस ड्राइवर ने अंत में हैमिल्टन के दबाव का बखूबी सामना किया। उन्हें फेरारी की टीम के भीतर चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी फायदा मिला। लैंडो नॉरिस (मैकलारेन) के भारी दबाव को झेलते हुए लेक्लेर चौथे स्थान पर रहे। उनके पीछे जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज) और पिट लेन से रेस में उतरे लियाम लॉसन (रेसिंग बुल्स) रहे। गैब्रिएल बोर्टोलेतो (ऑडी), रेड बुल के इसैक हजर - जिन्हें पहले ही लैप में रसेल की टक्कर के कारण स्पिन करना पड़ा था - और हास के लिए अपने एफ वन डेब्यू में उतरे यों हिराकावा (जिन्हें वीकेंड के बीच में बुलाया गया था) टॉप 10 में शामिल रहे।

विलियम्स के एलेक्स एल्बोन प्वाइंट्स के दायरे से ठीक बाहर रहे, जो अपने टीम के साथी कार्लोस सैन्ज से आगे थे। ऑस्कर पियास्त्री को लिंडब्लाड के साथ टक्कर के लिए 10 सेकंड की पेनल्टी मिली, जिससे वे खिसककर 13वें स्थान (पी13) पर आ गए।

वनडे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रही है कांटे की टक्कर

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होने जा रहा है। टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया। हालांकि, 50 ओवर के फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच काटे की टक्कर रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अब तक कुल 123 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 63 मैचों में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है।

वहीं, 52 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे सीरीज पिछले साल खेली गई थी, जिसमें कीवी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। हालांकि, टीम इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा है। न्यूजीलैंड में भारत ने अब तक कुल 45 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को सिर्फ 14 में जीत मिली है, जबकि 26 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज न्यूजीलैंड में साल 2022 में खेली थी, जिसे न्यूजीलैंड ने 1-0 से अपने नाम किया था। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल के सामने वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से पार पाने की कड़ी चुनौती होगी। वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि आखिरी दो एकदिवसीय मुकाबलों में टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी। भारत का बल्लेबाजी क्रम विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में काफी दमदार नजर आ रहा है। केएल राहुल, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर पर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी होगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड : कीवी टीम को लगा दोहरा झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुए दो खिलाड़ी

वेलिंगटन (एजेंसी)



न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज के आगाज से पहले दोहरा झटका लगा है। रचिन रवींद्र अपनी चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाने के चलते वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं, मार्क चैपमैन भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी इंजरी के कारण पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग के दौरान चैपमैन के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक बयान के अनुसार, हाल ही में हुए एमआरआई के बाद उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए अभी दो और हफ्तों के रिहैब की जरूरत है। दूसरी ओर, एक प्रमोशनल शूट के दौरान हुई एक घटना में रवींद्र के दाएं कंधे का जोड़ खिसक गया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान के मुताबिक, उन्हें पूरी क्षमता के साथ मैदान पर उतरने के लिए अभी और रिकवरी समय की जरूरत है। न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, हर कोई जानता है कि मार्क और रचिन इस टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं, इसलिए यह अफसोस की बात है कि उन्हें यह सीरीज छोड़नी पड़ रही है। पिछले हफ्ते मेरी मार्क से बात हुई थी। वह निराश जरूर हैं, लेकिन मैदान पर वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जहां तक रचिन की बात है, उनके कंधे में अभी तक इतना सुधार नहीं हुआ है कि वह वाइट-बॉल क्रिकेट में आराम से फील्डिंग कर सकें। इस वजह से इस महीने के आखिर में होने वाली टेस्ट सीरीज को देखते हुए हम कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहते।

सीफर्ट शुरुआती तीन मैचों के लिए टीम में शामिल

विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट को पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम में बुलाया गया है। उन्हें पहले ही सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए चुना गया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को भी टीम में शामिल किया गया है। निकोल्स को पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम में लिया गया है, जबकि फॉक्सक्रॉफ्ट आखिरी दो मैचों के लिए टीम से जुड़ेंगे।

तेज गेंदबाज मैट फिशर भी पहले तीन मैचों के लिए टीम का हिस्सा होंगे, जबकि शुरुआत में उन्हें केवल आखिरी दो वनडे मैचों के लिए चुना गया था। इस दौरान उनके खेलने की स्थिति का आकलन किया जाएगा। हेनरी अपनी दाईं जांघ की मांसपेशियों में हल्की चोट (लो-ग्रेड टियर) के कारण पिछले तीन टी20 मैचों से बाहर थे।

एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की दहलीज पर विराट कोहली, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

नई दिल्ली (एजेंसी)



टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने करियर के उस मुकाम पर हैं, जहां वह हर मैच के साथ ही कोई न कोई बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार (4 नवंबर) को होने वाले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भी विराट के पास एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। दरअसल, विराट कोहली वनडे में नंबर तीन की पोजीशन पर खेलते हुए अब तक 305 पारियों में 12,988 रन बना चुके हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर पहले वनडे मुकाबले में विराट 12 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह इस पोजीशन पर खेलते हुए 13 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज रिकी पोंटिंग मौजूद हैं, जिन्होंने 365 पारियों में 12,662 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में किसी एक पोजीशन पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 15,310 रन बनाए हैं। विराट कोहली अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक शतक लगाने में सफल रहते हैं, तो वो लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। कोहली और सचिन ने अभी तक लिस्ट-ए क्रिकेट में 60-60 शतक लगाए हैं। कोहली का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर की क्रिकेट में शानदार रहा है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड : कीवी टीम को किस बात का मिल सकता है फायदा? पुजारा ने बताया कारण

नई दिल्ली (एजेंसी)



पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाल में किए गए कुछ बदलावों के कारण मेहमान टीम को थोड़ा नुकसान होगा। पुजारा को यह भी लगता है कि पांच मैचों की सीरीज का कम से कम एक मैच बारिश के कारण रद्द हो सकता है।

वनडे सीरीज के परिणाम पर पुजारा का क्या है दावा

भारत को आखिरी दो वनडे मैचों में नियमित कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान केएल राहुल के बिना खेलना होगा, क्योंकि वे 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे। वनडे सीरीज 15 नवंबर को समाप्त होगी। पुजारा ने कहा, सीरीज का परिणाम 2-2 से बराबर रह सकता है। पहले तीन मैचों में एक ही भारतीय टीम खेल रही है लेकिन अंतिम दो वनडे में अलग टीम होगी।

इसलिए मुझे लगता है कि इससे न्यूजीलैंड को थोड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा, पहले तीन मैचों में मैं भारतीय टीम का पलड़ा भारी रह सकता है, लेकिन आखिरी दो मैच थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। दोनों टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में बारिश होती रहती है और इसलिए एक मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है।

रोहित-कोहली को लेकर क्या बोले पुजारा?

पुजारा से यह भी पूछा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन इस सीरीज में ज्यादा शतक बना सकता है। इस पूर्व टेस्ट विशेषज्ञ ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोहली ज्यादा शतक बनाएंगे। उन्होंने कहा, रोहित की पावरप्ले में अच्छी शुरुआत देने में अहम भूमिका होती है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड में उनकी यह भूमिका बदल जाए। ऐसा होता है तो वह शतक बना सकते हैं।

लेकिन विराट के लिए संभावनाएं थोड़ी अधिक हैं क्योंकि वह नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी मुख्य भूमिका पारी को संवारने वाले सूत्रधार की होगी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए वनडे प्रारूप में शतक बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी तय होती है लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में यह थोड़ी बदल जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में रोहित की तुलना में विराट के शतक बनाने की संभावना अधिक है।

टेस्ट सीरीज गंभीर के लिए निर्णायक होगी, हमें न्यूजीलैंड को उनके घर में हराना चाहिए : अभिषेक नायर

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम मैनेजमेंट को उन खिलाड़ियों के लिए रेड-बॉल (लाल गेंद) की तैयारी को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, जो दोनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। उनका तर्क है कि यह सीरीज हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अहम है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम को अलग-अलग हिस्सों में बांटने के फैसले पर नायर ने कहा कि अगर शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को लाल गेंद (रेड-बॉल) क्रिकेट की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलता, तो यह उनके लिए फायदेमंद होता। उन्होंने यह बात खास तौर पर इसलिए कही, क्योंकि भारत हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार चुका है। नायर ने माना कि भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड से मिली पिछली हार की याद अभी भी टीम के लिए निराशाजनक है। उनका मानना है कि भारतीय टीम को आगामी सीरीज में उसी जोश और आक्रामकता के साथ उतरना चाहिए और उस हार का करारा जवाब देना चाहिए। नायर ने जियोस्टार से कहा, न्यूजीलैंड भारत आई थी और उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज में हराया था। इससे मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई और हमारे बाकी फैंस को भी। इसी कारण यह एक बहुत बड़ी सीरीज है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। वर्ल्ड कप महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए अभी समय है।

मेरे हिसाब से यह टेस्ट सीरीज गौतम गंभीर और भारतीय फैंस के लिए एक निर्णायक सीरीज है। उन्होंने आगे कहा, इसी वजह से मैं चाहता था कि केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, जो दोनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, वे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान दें। इसका कारण यह है कि अब आपको वनडे के लिए तैयारी करनी है और उसके बाद टेस्ट के लिए। मेरी राय में उन्हें रेड-बॉल के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक-दो महीने का समय दिया जाना चाहिए था। जैसे उन्होंने (न्यूजीलैंड) हमें भारत में हराया, वैसे ही हमें उन्हें उनके घर में हराना चाहिए। भारत की पांच वनडे मैचों की सीरीज में कप्तानी की व्यवस्था अलग-अलग होगी। शुरुआती तीन मैचों में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मैचों की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे। तीसरे मैच के बाद गिल और राहुल वनडे टीम से हट जाएंगे, ताकि वह टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर सकें। नायर ने वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल के न चुने जाने पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस बाएं हाथ के ओपनर को बाहर बैठने के बजाय घरेलू क्रिकेट के जरिए अपनी 'रेड-बॉल' (टेस्ट क्रिकेट) की काबिलियत को और मजबूत करने का मौका दिया जा सकता था।

मेसी का शानदार प्रदर्शन, इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन को 2-1 से हराया

फॉक्सबोरो (एजेंसी)



लियोनेल मेसी ने एक बेहतरीन असिस्ट और मैच के आखिर में किए गए गोल की मदद से इंटर मियामी को न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के खिलाफ 2-1 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही टीम ने अगले साल होने वाले कॉन्काकैफ चैंपियंस कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत से मियामी एमएलएस कप प्लेऑफ से पहले ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में नंबर 2 सीड की स्थिति में पहुंच गई है।

इस सीजन में मेसी के नाम अब 26 गोल और 16 असिस्ट हो गए हैं। इसके साथ ही वह लगातार तीसरी बार एमएलएस एमवीपी अवार्ड और लगातार दूसरी बार 'गोल्डन बूट' जीतने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं। पहले 45 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला रहा और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस दौरान इंटर मियामी को 28वें मिनट में एक अच्छा मौका मिला, जब मेक्सिकन खिलाड़ी बर्टेरामे ने बॉक्स के बाईं ओर से बाएं पैर से शॉट मारा, जिसे न्यू इंग्लैंड के गोलकीपर मैट टर्नर ने बचा लिया। दूसरे हाफ में, 53वें मिनट में डेनियल गाजदाग के गोल की बदौलत मेजबान टीम (न्यू इंग्लैंड) ने खाता खोला। 69वें मिनट में इंटर मियामी ने शानदार टीम वर्क दिखाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। सेगोविया ने बॉक्स के अंदर एक 'लॉब' पास दिया, जिस पर मेसी ने हेडर से गेंद को बर्टेरामे की तरफ बढ़ाया।

बर्टेरामे ने बॉक्स के बीच से एक जोरदार हेडर लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। यह इस रेगुलर सीजन में बर्टेरामे का 10वां गोल था, जबकि मेसी का यह इस लीग सीजन का 16वां असिस्ट रहा। 83वें मिनट में इंटर मियामी ने मैच का पासा पूरी तरह से पलटा। एक बेहतरीन पासिंग सीक्वेंस के बाद मेसी ने निर्णायक गोल किया। सुआरेज ने बॉक्स के बाहर बीच में मेसी को गेंद दी, जहां अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी ने तीन डिफेंडरों को छकाया। इसके बाद सेगोविया के साथ मिलकर वह बॉक्स के अंदर पहुंचे और एक सटीक शॉट के जरिए गेंद को गोल पोस्ट के निचले दाएं कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ मेसी के कुल गोल की संख्या 26 हो गई है, जिससे वह एमएलएस 2026 गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। वहीं, इस रेगुलर सीजन में सेगोविया के असिस्ट की संख्या 12 हो गई है। इसके बाद 1-2 की स्कोरलाइन अंतिम सीटी बजने तक कायम रहा, जिससे इंटर मियामी ने अपने घर से बाहर खेलते हुए तीन अंक हासिल किए।

शीर्ष पर पहुंचा आर्सेनल, चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ दर्ज की 2-0 से जीत

लंदन (एजेंसी)



काई हैवर्ट्ज के एकमात्र गोल की मदद से आर्सेनल ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर प्रीमियर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। जर्मन फॉरवर्ड ने डेक्लान राइस के सटीक पास पर 16वें मिनट में गोल दागा। मैच के बाकी समय में लिवरपूल ने बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन 15 से ज्यादा शॉट लेने के बावजूद वह आर्सेनल के अनुशासित डिफेंस को नहीं तोड़ पाए। शनिवार को मैनचेस्टर सिटी को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। ब्राइटन के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर उन्हें 1-0 से हार मिली। मैथियस नून्स से क्लीयरेंस में गलती हुई, जिसका फायदा उठाते हुए यासिन अयारी ने 11वें मिनट में गोल किया।

मैनचेस्टर सिटी अब स्टैंडिंग में आर्सेनल से तीन अंक पीछे दूसरे स्थान पर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में माइकल कैरिक की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि उनकी टीम को चेल्सी के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले हाफ में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन 50वें मिनट में मॉर्गन रोजर्स के शानदार व्यक्तिगत गोल के कारण वह पिछड़ गए। इसके बाद लिसेंड्रो मार्टिनेज को दूसरा पीला कार्ड मिलने और पेनल्टी देने के कारण रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। 64वें मिनट में कोल पामर ने पेनल्टी पर गोल दागकर चेल्सी की बढ़त 2-0 कर दी। इस हार के साथ कैरिक की टीम 1988 के बाद पहली बार इतने लंबे समय तक जीत दर्ज करने में नाकाम रही है।

आलिया भट्ट ने छठी क्लास में शुरू कर दी थी डेटिंग, 'कॉफी विद करण' पर सुनाया था वाकया

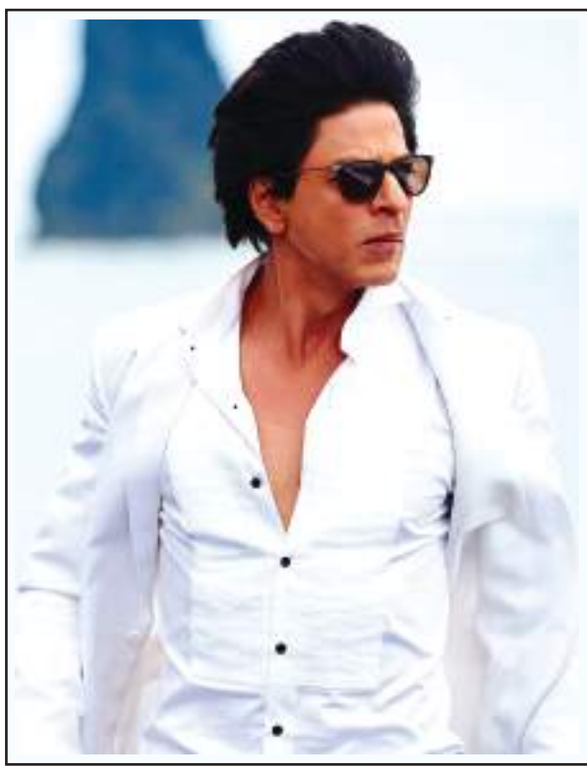


एक्ट्रेस आलिया भट्ट पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' में कई बार आ चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने इस चैट शो में 2013 में अपने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के को-स्टार्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ डेब्यू किया था। इस एंटरटेनिंग एपिसोड के दौरान, आलिया ने होस्ट और फिल्ममेकर करण जौहर समेत सभी को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने क्लास 6 में डेटिंग शुरू कर दी थी। करण ने कहा कि वरुण ने उन्हें बताया कि आलिया के बचपन में कई यंग बॉयफ्रेंड थे। हालांकि, इस पर मजाकिया अंदाज में आपत्ति जताते हुए आलिया ने कहा, मैं इसे कोई सिलसिला नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे (बॉयफ्रेंड) और सीरियस रिलेशनशिप थे, जैसे दो साल, (फिर) दो साल। करण ने इस बात पर हैरानी जताई कि आलिया 17 साल की उम्र तक दो सीरियस रिलेशनशिप में रह चुकी थीं। करण जौहर ने पूछा, आपने 10 साल की उम्र में डेटिंग शुरू कर दी थी? आलिया ने हंसकर जवाब देते हुए कहा, इसीलिए मैं कहती हूं कि यह कोई डोरी नहीं है। मैंने छठी क्लास में डेटिंग शुरू कर दी थी। जब हैरान करण ने उनसे पूछा, क्या?, आलिया ने जवाब दिया, लेकिन, जाहिर है कि यह डेटिंग नहीं थी। यह तो बस ऐसा था, जैसे हम क्लासरूम की दूसरी तरफ से एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। वरुण ने फिर मजाक में कहा कि यह 'आधा-आधा' था, जिस पर आलिया ने कहा, कुछ भी आधा-अधूरा नहीं था। असल में मेरा पहला बॉयफ्रेंड 10वीं क्लास में था। यह बताते हुए कि यह एक सीरियस रिलेशनशिप था, आलिया ने कहा, क्योंकि मैंने उसे दो साल तक डेट किया। वह मेरा पहला, हाई-स्कूल जैसा प्यार था। करण ने आलिया से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने उन्हें इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि वह एक्टर बनना चाहती थीं। इस बात से इनकार करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया।' आलिया की लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 14 अप्रैल, 2022 को एक्टर रणबीर कपूर से शादी कर ली। नवंबर 2022 में इस लवबर्ड्स ने अपनी बेटी राहा कपूर का स्वागत किया। **(एजेंसी)**

'दीपावली मनाना हमें दीया मिर्जा से सीखने की जरूरत नहीं', भाजपा नेताओं ने अभिनेत्री पर साधा निशाना

मुंबई में दीपावली पर प्रदूषण कम करने की अपील को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया है। अभिनेत्री दीया मिर्जा के दीपावली के संदेश पर पहले मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद बीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनका वीडियो हटा दिया था। अब केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भाजपा नेता श्रीकांत भारतीय और विधायक संजय उपाध्याय ने भी मामले पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने दीया मिर्जा के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'दीया दूसरे धर्म से आती हैं और उन्हें त्योहार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को अपने-अपने त्योहार मनाने का अधिकार देता है। पटाखों के बिना दीपावली मनाने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि इस दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि ज्यादा प्रदूषण न हो। इसके लिए गाइडलाइन पहले ही जारी की गई हैं और उनके तहत कुछ पटाखे जलाए जा सकते हैं।' आठवले ने दीया के इस तरह त्योहार को लेकर बयान देने को गलत बताया और कहा कि इससे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने अभिनेत्री के बयान का विरोध भी किया। बीजेपी नेता श्रीकांत भारतीय ने भी दीया मिर्जा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'दीया मिर्जा को दूसरों को दीपावली मनाने का तरीका बताने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। हालांकि हमारी पार्टी किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन दीया को अपने धर्म से जुड़े त्योहारों और परंपराओं पर भी बात करनी चाहिए। हिंदू समाज सदियों से पर्यावरण की चिंता करता आया है। कौन से पटाखे जलाने चाहिए और दीपावली किस तरह मनानी चाहिए, यह देश के लोगों को पता है। इसके लिए उन्हें दीया मिर्जा से सीख लेने की जरूरत नहीं है।' बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने इस विवाद को दूसरे हिंदू त्योहारों से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'दीया मिर्जा को दीपावली के पटाखों से दिक्कत है। कुछ बॉलीवुड हस्तियां और तथाकथित बुद्धिजीवी हर बार हिंदू त्योहारों के दौरान किसी न किसी मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। होली के समय पानी की खपत, दही हांडी के दौरान सुरक्षा, नवरात्रि में शोर और गणेशोत्सव के समय प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को लेकर सवाल किए जाते हैं।' उन्होंने आगे कहा, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान, अमेरिका तथा इजरायल के बीच तनाव में भी बम और गोले गिरने से बड़े स्तर पर तबाही हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। **(एजेंसी)**





जब एक रोल के लिए शाहरुख खान को कटवाने पड़े थे लंबे बाल, दुखी मन से मानी थी शर्त

सिनेमा के इतिहास में कुछ ही ऐसे चेहरे होते हैं, जो पर्दे पर आते ही समय की धारा को मोड़ देते हैं। आज जिसे पूरी दुनिया 'किंग खान' बुलाती है और उनकी हेयरस्टाइल के लाखों दीवाने रहते हैं लेकिन उनके करियर की शुरुआत में एक ऐसा वक्त भी आया था, जब अभिनेता को अपने बालों को कटाना पड़ा था। यह दौर तब का है जब शाहरुख अभिनय की दुनिया में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। आज भले ही लंबे बाल और उनका सिग्नेचर हेयरस्टाइल उनकी पहचान बन चुका हो लेकिन संघर्ष के शुरुआती दिनों में निर्माताओं और निर्देशकों की शर्तों के आगे उन्हें अपनी पसंद से समझौता करना पड़ा था। आखिर क्या थी वो मजबूरी और किस फिल्म या प्रोजेक्ट के दौरान शाहरुख को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा था? आइए जानते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में... 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अभिनेता शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहा जाता है लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 90 के दशक में जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था, तो किसी भी बड़े हीरो ने विलेन का रोल करने से परहेज किया था। उस दौर में शाहरुख ने बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल से दर्शकों के मन में खौफ पैदा किया और फिर हीरो बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया। शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स किया था। इस दौरान वे दिल्ली के 'थिएटर एक्शन ग्रुप' से जुड़े और प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के मार्गदर्शन में अभिनय सीखा। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में पीजी में दाखिला लिया था लेकिन अभिनय करने के जुनून के चलते अभिनेता ने अपना पीजी बीच में छोड़ दिया था। बताया जाता है कि माता-पिता के देहांत के बाद बड़ा मुकाम हासिल करने की इच्छा लेकर शाहरुख साल 1991 में दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए थे। अभिनेता रंगमंच में सक्रिय थे, जहां पर उनके स्वाभाविक अभिनय और जबरदस्त ऊर्जा ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शाहरुख खान को कैमरे के सामने अभिनय करने का सबसे पहला ब्रेक जाने-माने निर्देशक लेख टंडन ने अपने धारावाहिक 'दिल दरिया' में दिया था। हालांकि, इस शो में काम करने के लिए निर्देशक ने अभिनेता के सामने एक अजीब-सी शर्त रख दी थी। उन्होंने शाहरुख से अपने लंबे और बिखरे बाल कटवाने के लिए कहा था। शाहरुख को अपने बालों से बहुत प्यार था लेकिन अभिनय के जुनून के कारण उन्होंने दुखी मन से इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने बाल कटवा लिए। **(एजेंसी)**



सुकेश चंद्रशेखर केस : 'कोर्ट को हल्के में न लें', नोरा नहीं हुईं पेश तो अदालत ने लगाई फटकार

200 करोड़ की ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेकर से जुड़े इस मामले में अदालत ने नया आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नोरा फतेही को सबूत के लिए सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने के लिए नया समन जारी किया। वह सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े एक एक्सटॉर्शन केस में गवाह हैं। स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने नोरा फतेही को नया समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोरा फतेही को इस मामले में गवाह के तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 02 नवंबर 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किया था। मगर, अभिनेत्री पेश नहीं हुईं। इसके बाद अदालत ने नोरा के व्यवहार पर सवाल उठाया है। साथ ही कहा कि वे कोर्ट को हल्के में न लें। नोरा की तरफ से उनके वकील ने अर्जी दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नोरा फतेही को बुलाया गया है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे आ रही हैं या नहीं। उनके वकील पेश हुए और छूट के लिए अर्जी दी। कोर्ट ने वकील को फटकार लगाई और कहा कि वह (नोरा) एक गवाह हैं और उन्हें यहां होना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, 'उनका व्यवहार ठीक नहीं है। कोर्ट को हल्के में न लें'। कोर्ट ने वकील से पूछा कि उन्हें कब बुलाया गया था। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें 29 अक्टूबर को बताया गया था। **(एजेंसी)**

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला वेदांत पॉली फैब्स का आईपीओ, 9 नवंबर को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)



फ्लैक्सिबल पैकेजिंग मैटेरियल्स का निर्माण करने और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को 3-लेयर तथा 5-लेयर एलडी फिल्म्स, श्रिंक फिल्म्स, बैरियर फिल्म्स, प्रिंटेड लैमिनेट्स सहित मिल्क एवं ऑयल पाउच की आपूर्ति करने वाली कंपनी वेदांत पॉली फैब्स लिमिटेड का 56.68 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया।

कंपनी मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) मॉडल पर काम करती है। लॉन्चिंग के बाद दोपहर 11:30 बजे तक इस आईपीओ को 18 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के इस आईपीओ में निवेशक 4 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 5 नवंबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 6 नवंबर को अलॉटेड शेयर सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी दिन जिन निवेशकों को शेयर का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कंपनी के शेयर 9 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 88 से लेकर 94 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयरों का है। रिटेल इंवेस्टर्स इस इश्यू में कम से कम दो लॉट यानी 2,400 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 2,25,600 रुपये का निवेश करना होगा।

इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 60.30 लाख शेयर जारी किए जा रहे हैं। इस इश्यू के तहत 51.01 करोड़ रुपये मूल्य के 54.26 लाख नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, जबकि प्रमोटर सेथसावरिया पॉली फैब एलएलपी द्वारा 5.67 करोड़ रुपये मूल्य के 6.04 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए की जा रही है। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए कुल नेट ऑफर का 1.19 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है।

इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा यानी 59.32 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 39.49 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस पूरे इश्यू के लिए एफिनिटी ग्लोबल कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि कैमीओ कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

लागत पर ध्यान, विमानन उद्योग की चुनौतियों से निपटने को तैयार इंडिगो : वॉल्श

नई दिल्ली (एजेंसी)

इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विली वॉल्श ने सोमवार को कहा कि कंपनी को कई अवसर दिख रहे हैं और वह विमानन उद्योग की चुनौतियों से निपटेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विमानन कंपनी का ध्यान लागत आधार को बेहतर बनाए रखने पर है। अगस्त में सीईओ का पदभार संभालने के बाद वॉल्श ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखी और कहा कि विमानन कंपनी को 2028 की दूसरी तिमाही से चौड़े आकार वाले ए350 विमान मिलने शुरू होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की उड़ानों के बाजार में सफल होने के लिए विमानन कंपनी के पास सभी आवश्यक खूबियां हैं। ए350 विमानों में तीन श्रेणियों वाली सीट व्यवस्था होगी। इसमें बिजनेस श्रेणी में पूरी तरह 'बेड' बन जाने वालीं 16 सीट के साथ प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी श्रेणी की सीट होंगी। ईंधन की बढ़ती कीमतों से विमानन कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित होने के बीच वॉल्श ने कहा कि उद्योग के लिए मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है और इंडिगो इन चुनौतियों से निपटेगी। ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव की रणनीति (हेजिंग) के बारे में वॉल्श ने कहा कि फिलहाल इसे शुरू करने की कोई योजना नहीं है। नीति को अंतिम रूप देने के बाद इस विकल्प पर विचार किया जाएगा। इंडिगो को जुलाई-सितंबर तिमाही में 1,879.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। ईंधन की ऊंची लागत और रुपये के मूल्य में गिरावट से उसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विमानन कंपनी ने अपनी क्षमता भी घटाई थी। उन्होंने कहा, हमें जबरदस्त अवसर दिख रहे हैं।

भारत, यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। इस समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर होने हैं। आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले सप्ताह ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की। अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा महानिदेशालय की डिट्टे जुल जॉर्गनस, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी महानिदेशालय के कोएन डोएन्स और कराधान एवं सीमा शुल्क संघ महानिदेशालय के गेरासिमोस थॉमस से मुलाकात की।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इन बैठकों में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रालय ने कहा, 'दोनों पक्षों ने कारोबारियों को समर्थन देने, लेनदेन की लागत कम करने और वैध व्यापार की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने में कुशल, पारदर्शी एवं डिजिटल रूप से सक्षम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के महत्व को स्वीकार किया।' दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को इस समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी। इससे चमड़ा, कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सचिव ने हीरा उद्योग के हितधारकों से मुलाकात की। इनमें एंटवर्प के हीरा कारोबार से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल थे।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों की रफ्तार अक्टूबर में घटी

नई दिल्ली (एजेंसी)

अक्टूबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई। उत्पादन एवं नए ऑर्डर में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। वहीं, लागत का दबाव मध्यम रहने से गतिविधियों की रफ्तार धीमी होने का असर सीमित रहा।

सोमवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर के 55.1 से घटकर अक्टूबर में 54.7 पर आ गया। हालांकि, यह अब भी अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर और 50 के तटस्थ स्तर से काफी अधिक रहा।



क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में 50 से ऊपर का अंक विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन का संकेत देता है। सर्वेक्षण में कहा गया कि मांग में लगातार सुधार से नए कारोबार में एक बार फिर तेज वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि की रफ्तार सितंबर के सात महीने के उच्च स्तर से मामूली ही धीमी हुई और ऐतिहासिक मानकों के लिहाज से मजबूत बनी रही। अक्टूबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत विस्तार जारी रहा, हालांकि उत्पादन एवं नए ऑर्डर में वृद्धि की रफ्तार कुछ कम रही। कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और भंडार जमा करना जारी रखा, हालांकि नियुक्तियों की गति धीमी रही और कारोबारी भरोसा कमजोर हुआ।

एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, 'भारत का विनिर्माण पीएमआई पिछले महीने के 55.1 से घटकर अक्टूबर में 54.7 पर आ गया, लेकिन यह मजबूती से विस्तार के दायरे में और अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बना रहा।' भंडारी ने कहा, 'मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण नए निर्यात ऑर्डर में वृद्धि छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिससे उत्पादन में मजबूत बढ़ोतरी को समर्थन मिला। उत्पादकों ने कच्चे माल का भंडार भी आठ महीने में सबसे अधिक बढ़ाया। उन्होंने अस्थिर वैश्विक माहौल में संभावित कमी से निपटने और उत्पादन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एहतियाती भंडार तैयार किया।'

कंपनियों ने बांग्लादेश, कनाडा, इंडोनेशिया, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों से कारोबार में बढ़ोतरी की जानकारी दी। रोजगार के मोर्चे पर, उत्पादन की अधिक जरूरत एवं काम का बोझ बढ़ने से कारखानों में लगातार दूसरे महीने रोजगार बढ़ा, हालांकि नई नौकरियां देने की रफ्तार धीमी हुई।